गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 223
दि. 14.12.2025,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

बंगाल में मतदाता सूची की शुद्धता के लिए बड़ा अभियान, हर विधानसभा में रोज़ 100 वोटरों की सुनवाई

(जीएनएस)। कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने एक व्यापक और सख्त अभियान की शुरुआत की है। आयोग ने निर्णय लिया है कि अब राज्य की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रतिदिन कम से कम 100 मतदाताओं की सुनवाई की जाएगी। इससे पहले यह संख्या 50 प्रतिदिन निर्धारित थी, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है। आयोग का मानना है कि इस कदम से मतदाता सूची में मौजूद त्रुटियों, फर्जी प्रविष्टियों और संदिग्ध आंकड़ों को समयबद्ध तरीके से सुधारा जा सकेगा और चुनावी प्रक्रिया पर जनता का भरोसा और मजबूत होगा।

इस पूरे अभियान की जिम्मेदारी सह निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों यानी ईआरओ को सौंपी गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 एईआरओ नियुक्त किए गए हैं। इस तरह राज्य के 294 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 2940 एईआरओ इस कार्य में लगाए गए हैं। इसके अलावा, काम के बढ़ते दबाव और सुनवाई की प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा करने के लिए 1000 से 1500 अतिरिक्त एईआरओ भी नियुक्त किए जा रहे हैं। आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से न छूटे और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में न रहे।

चुनाव आयोग के अनुसार, सुनवाई के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार के मतदाताओं को बुलाया जाएगा। पहली श्रेणी में वे मतदाता शामिल हैं जिन्हें 'नान-मैपिंग' वोटर कहा जा रहा है।

ऐसे करीब 30 लाख मतदाता हैं जिनका नाम या उनके किसी करीबी रिश्तेदार का नाम वर्ष 2002 की पिछली मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। उल्लेखनीय है कि 2002 वह वर्ष था जब राज्य में आखिरी बार विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर किया गया था। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन सभी नान-मैपिंग मतदाताओं को अनिवार्य रूप से सुनवाई के लिए उपस्थित होना होगा, ताकि उनकी पहचान और पात्रता की पूरी तरह पुष्टि की जा सके।

दूसरी श्रेणी में वे मतदाता हैं जिनका डेटा संदिग्ध पाया गया है। आयोग के अनुसार, लगभग 1 करोड़ 67 लाख 45 हजार 911 मतदाताओं के रिकॉर्ड में ऐसी विसंगतियां पाई गई हैं, जिन पर संदेह जताया गया है। कई मामलों में मतदाता की उम्र और उनके माता-पिता या दादा-दादी की उम्र के बीच का अंतर असामान्य पाया गया है, जिससे डेटा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे मामलों में बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ संबंधित मतदाताओं के घर जाकर दोबारा सत्यापन करेंगे। यदि बीएलओ को सत्यापन के दौरान संतोषजनक जानकारी नहीं मिलती है, तो उन मतदाताओं को भी औपचारिक सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा।

आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया का एक स्पष्ट समयबद्ध खाका भी तैयार किया है। आगामी 16 दिसंबर को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद मतदाताओं को यह अवसर दिया जाएगा कि वे सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि, आपत्ति या सुधार के लिए आवेदन कर सकें। इन आपत्तियों और दावों के आधार पर भी सुनवाई की जाएगी। सभी प्रक्रियाओं और जांच के बाद अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी, जिसे पूरी तरह सत्यापित और अद्यतन माना जाएगा।

इस बीच चुनाव आयोग ने बंगाल में बीएलओ और अन्य चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग को विभिन्न स्रोतों से ऐसी सूचनाएं मिली हैं, जिनमें चुनावी कार्य से जुड़े अधिकारियों की सुरक्षा को खतरा बताया गया है। आयोग ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया है कि बीएलओ या किसी भी चुनाव अधिकारी के खिलाफ हिंसा की प्रत्येक घटना पर तुरंत एफआईआर दर्ज कराई जाए। आयोग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी जिले में इस प्रकार की घटना के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो इसे अत्यंत गंभीर लापरवाही माना जाएगा और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में चुनाव से जुड़े अधिकारियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। इससे पहले 28 नवंबर 2025 को आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को भी पत्र लिखकर यह जानकारी दी थी कि बीएलओ और चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों के जीवन को लेकर स्पष्ट खतरे की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। आयोग ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वे सभी संभावित उपाय करें ताकि चुनावी कार्य करने वाले अधिकारियों को किसी भी प्रकार के डर, धमकी या अनुचित दबाव का सामना न करना पड़े।

चुनाव आयोग का मानना है कि मतदाता सूची की शुद्धता और चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा, दोनों ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद हैं। इसी सोच के तहत बंगाल में यह व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आने वाले चुनाव पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ संपन्न हो सकें।

महाराष्ट्र की रफ्तार को मिलेगी नई उड़ान, नितिन गडकरी ने 1.5 लाख करोड़ की सड़क परियोजनाओं को दी हरी झंडी

(जीएनएस)। महाराष्ट्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये की विशाल सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी देकर विकास की नई तस्वीर पेश की है। नागपुर में आयोजित विधानसभा परिषद के शताब्दी समारोह के दौरान की गई इस घोषणा को राज्य के आर्थिक और औद्योगिक भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गडकरी ने स्पष्ट किया कि ये सभी परियोजनाएं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत की गई हैं और अगले तीन महीनों के भीतर इन पर काम शुरू हो जाएगा, जबकि कई परियोजनाओं को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल सड़कों का निर्माण नहीं, बल्कि पूरे राज्य में आवागमन को तेज, सुरक्षित और सुगम बनाना है। इससे उद्योग, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। गडकरी ने कहा कि अच्छी सड़कें केवल दूरी नहीं घटातीं, बल्कि समय, ईंधन और लागत की भी बचत करती हैं, जिससे आम नागरिक और कारोबारी दोनों को सीधा लाभ मिलता है।

घोषित परियोजनाओं में सबसे प्रमुख पुणे–छत्रपति संभाजीनगर एक्सप्रेसवे है, जिसे 16,318 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण महाराष्ट्र राज्य अवसंरचना विकास निगम द्वारा किया जाएगा और इसके लिए एमओयू पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं। इस सड़क के बन जाने से पुणे और छत्रपति संभाजीनगर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र दो घंटे रह जाएगा, वहीं छत्रपति संभाजीनगर से नागपुर की दूरी ढाई घंटे में तय की जा सकेगी। यह परियोजना मराठवाड़ा और विदर्भ को पुणे जैसे औद्योगिक केंद्र से सीधे जोड़कर क्षेत्रीय विकास को नई गति देगी।

पुणे शहर और उसके आसपास यातायात की समस्या को देखते हुए एलिवेटेड रोड परियोजनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। 4,207 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली तलेगांव–चाकन–शिकरापुर एलिवेटेड रोड को जल्द शुरू करने की घोषणा की गई है। गडकरी ने बताया कि स्थानीय निकाय चुनावों के बाद इसका भूमि पूजन किया जाएगा। यह सड़क औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और भारी वाहनों की आवाजाही को आसान बनाएगी। इसके साथ ही हडपसर–यावत एलिवेटेड रोड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है और चुनावों के बाद इस पर भी काम शुरू होने की संभावना है।

पुणे क्षेत्र को लेकर गडकरी ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि यहां सड़क निर्माण कार्यों के लिए कुल 50,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। अगले तीन महीनों के भीतर इन परियोजनाओं पर काम शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा पुणे–मुंबई मार्ग के समानांतर एक नया एक्सप्रेसवे भी प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 15,000 करोड़ रुपये होगी। इस नए एक्सप्रेसवे के बन जाने से पुणे और मुंबई के बीच यात्रा का समय घटकर करीब डेढ़ घंटे रह जाएगा, जिससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों और व्यापारिक गतिविधियों को बड़ी राहत मिलेगी।

कुल मिलाकर, नितिन गडकरी द्वारा घोषित ये सड़क परियोजनाएं महाराष्ट्र के परिवहन ढांचे को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। बेहतर कनेक्टिविटी से न केवल शहरों के बीच दूरी घटेगी, बल्कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। सरकार को उम्मीद है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से महाराष्ट्र की आर्थिक रफ्तार और तेज होगी और राज्य देश के सबसे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा।

राजकुमार गोयल को सौंपी गई सूचना के प्रहरी की जिम्मेदारी, केंद्रीय सूचना आयोग को मिलेगा नया नेतृत्व

(जीएनएस)। देश की सूचना व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए पूर्व कानून एवं न्याय सचिव राज कुमार गोयल को देश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। लंबे समय से रिक्त चल रहे इस संवैधानिक पद पर अब अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी की तैनाती से केंद्रीय सूचना आयोग को नई दिशा और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सोमवार को उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी, जिसके साथ ही वह औपचारिक रूप से अपने कार्यभार का दायित्व संभाल लेंगे। राज कुमार गोयल का चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर किया गया है। यह समिति देश में सूचना के अधिकार से जुड़े शीर्ष पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को संवैधानिक दायरे में पूरा करती है। समिति द्वारा उनके नाम पर सहमति बनने के बाद केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति को अंतिम रूप दिया। प्रशासनिक हलकों में यह नियुक्ति अनुभव और संतुलन का मेल मानी जा रही है, क्योंकि गोयल ने अपने लंबे सेवा काल में शासन और कानून दोनों क्षेत्रों में गहरी समझ विकसित की है। राज कुमार गोयल 1990 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने 31 अगस्त को कानून एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत न्याय विभाग में सचिव पद से सेवानिवृत्ति ली थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण विधायी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को नजदीक से देखा और संचालित किया। इससे पहले वे गृह मंत्रालय में सचिव (सीमा प्रबंधन) के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, जहाँ देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमावर्ती प्रबंधन से जुड़े अहम निर्णयों में उनकी भूमिका रही। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार और तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य में भी उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाई हैं, जिससे उनका प्रशासनिक अनुभव और अधिक व्यापक हो गया।

मुख्य सूचना आयुक्त का यह पद तब रिक्त हुआ था जब वर्तमान सीआईसी हीरालाल सामरिया का कार्यकाल 13 सितंबर को पूरा हो गया था। उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद केंद्रीय सूचना आयोग में शीर्ष नेतृत्व का अभाव महसूस किया जा रहा था। ऐसे में राज कुमार गोयल की नियुक्ति को आयोग के लिए एक स्थायित्व देने वाला निर्णय माना जा रहा है, क्योंकि उनके अनुभव से आयोग के कामकाज में संतुलन और निरंतरता आने की उम्मीद है। केवल मुख्य सूचना आयुक्त ही नहीं, बल्कि केंद्रीय सूचना आयोग को और मजबूत करने के लिए आठ नए सूचना आयुक्तों के नामों पर भी मुहर लगा दी गई है। चयन समिति ने जिन नामों की अनुशंसा की है, उनमें प्रशासन, पुलिस सेवा, रेलवे, वन सेवा, पत्रकारिता और विधि क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोग शामिल हैं। इस सूची में पूर्व रेलवे बोर्ड अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा, पूर्व आईपीएस अधिकारी स्वागत दास, केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी संजीव कुमार जिंदल, पूर्व आईएएस अधिकारी सुरेंद्र सिंह मीना और पूर्व भारतीय वन सेवा अधिकारी खुशवंत सिंह सेठी के नाम प्रमुख हैं। इन सभी के पास शासन और प्रशासन का लंबा अनुभव है, जो सूचना आयोग के कार्यों को मजबूती देगा।

इसके अलावा इस बार पत्रकारिता और विधि क्षेत्र से जुड़े नामों को भी सूचना आयुक्त के रूप में चुना गया है। वरिष्ठ पत्रकार पी.आर. रमेश, आशुतोष चतुर्वेदी और सुधा रानी रेलंगी को भी इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए चयनित किया गया है। सुधा रानी रेलंगी इससे पहले सीबीआई में प्रॉसिक्यूशन डायरेक्टर और कानून एवं न्याय मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में सेवाएं दे चुकी हैं, जिससे उनका कानूनी अनुभव सूचना आयोग के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

अधिकारियों के अनुसार, नए नियुक्त सभी सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त राज कुमार गोयल के साथ ही पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इन नियुक्तियों से केंद्रीय सूचना आयोग में लंबे समय से चली आ रही रिक्तियों को भरने में मदद मिलेगी। साथ ही यह भी उम्मीद की जा रही है कि इससे आरटीआई से जुड़े लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और सूचना के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

आलंद सीट पर वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ का बड़ा खुलासा, 22 हजार पन्नों की चार्जशीट से सियासी हलकों में हलचल

(जीएनएस)। कर्नाटक की राजनीति में आलंद विधानसभा सीट से जुड़ा वोटर लिस्ट गड़बड़ी मामला एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। इस मामले में गठित विशेष जांच टीम ने शनिवार को एडीशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में करीब 22 हजार पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट ने न सिर्फ जांच की व्यापकता को उजागर किया है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में कथित साजिशों और सुनियोजित प्रयासों की गंभीर तस्वीर भी सामने रखी है। एसआईटी की जांच में कर्नाटक के पूर्व बीजेपी विधायक सुभाष गुट्टेदार और उनके बेटे हर्षानंद को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जिन पर वोटर लिस्ट से वैध मतदाताओं के नाम हटवाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। चार्जशीट के मुताबिक, यह मामला केवल एक-दो लोगों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। जांच एजेंसी ने सुभाष गुट्टेदार के निजी सचिव टिप्परुद्र को भी इस साजिश में शामिल बताया है। इसके अलावा कलबुर्गी के तीन डेटा सेंटर ऑपरेटर अकरम पाशा, मुकरम पाशा और मोहम्मद अशफाक तथा पश्चिम बंगाल के बापी आद्या पर भी इस पूरे मामले में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया है। चार्जशीट में दावा किया गया है कि इन सभी ने मिलकर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में हेरफेर करने की योजना बनाई और उसे अंजाम देने की कोशिश की।

एसआईटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आलंद विधानसभा क्षेत्र में करीब 5,994 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने का प्रयास किया गया था। इसके लिए कलबुर्गी में बाकायदा एक कॉल सेंटर नेटवर्क तैयार किया गया था, जहां से फर्जी डिलीशन एप्लिकेशन डाली जा रही थीं। इन एप्लिकेशनों के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि संबंधित मतदाता या तो स्थानांतरित हो चुके हैं या फिर उनके नाम गलत तरीके से सूची में दर्ज हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि यह सब सुनियोजित तरीके से किया गया ताकि एक खास वर्ग के मतदाताओं को मतदान से वंचित किया जा सके।

इस पूरे मामले ने उस समय राजनीतिक रूप से और तूल पकड़ लिया था, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 18 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान आलंद सीट पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने दावा किया था कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस समर्थक वोटरों को निशाना बना रहा है और उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। उनके इन आरोपों के बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया था।

अब 22 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल होने के बाद यह मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर और गंभीर होता नजर आ रहा है। जांच एजेंसियों का कहना है कि चार्जशीट में कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा, गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्य शामिल किए गए हैं, जो इस कथित साजिश की ओर इशारा करते हैं। अदालत में अब इस मामले की सुनवाई के दौरान यह तय होगा कि आरोपियों की भूमिका कितनी गहरी थी और क्या वास्तव में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी।

केरल में लेप्टोस्पायरोसिस का बढ़ता संकट, 2025 में अब तक 3259 मामले और 209 मौतों से दहशत

(जीएनएस)। केरल में लेप्टोस्पायरोसिस एक बार फिर गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभरकर सामने आया है। साल 2025 में इस बीमारी ने राज्य में भारी तबाही मचाई है, जहाँ अब तक हजारों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और सैकड़ों की जान जा चुकी है। केंद्र सरकार ने संसद में इस बीमारी से जुड़े ताजा और चिंताजनक आंकड़े साझा करते हुए अलर्ट जारी किया है, जिससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि 1 जनवरी से 5 दिसंबर 2025 के बीच केरल में लेप्टोस्पायरोसिस के 3259 पक्के मामले दर्ज किए गए हैं। इसी अवधि में इस बीमारी के कारण 209 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि राज्य में यह बीमारी अब केवल मौसमी समस्या नहीं रह गई है, बल्कि एक गंभीर और जानलेवा संकट का रूप ले चुकी है।

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केरल के सभी 14 जिलों में लेप्टोस्पायरोसिस के मामले सामने आए हैं, लेकिन कुछ जिले सबसे अधिक प्रभावित रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में सबसे ज्यादा 583 मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे यह जिला सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बन गया है। इसके बाद एर्नाकुलम में 492 और त्रिशूर में 340 मामले सामने आए हैं। इन जिलों में लगातार बारिश, जलभराव और गंदे पानी के संपर्क में आने की घटनाओं को बीमारी के फैलाव का प्रमुख कारण माना जा रहा है।

जेपी नड्डा ने यह भी स्पष्ट किया कि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए इस तरह की बीमारियों की निगरानी, रिपोर्टिंग और रोकथाम की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। हालांकि केंद्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और तकनीकी व नीतिगत सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि लेप्टोस्पायरोसिस एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जो खासतौर पर मानसून के मौसम में तेजी से फैलती है। केरल में लंबे समय से इसे एक स्थानिक बीमारी माना जाता है, क्योंकि हर साल बरसात के दौरान इसके मामले सामने आते हैं। केंद्र सरकार इस बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के माध्यम से लेप्टोस्पायरोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम चला रही है। यह कार्यक्रम देश के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है, जहाँ इस बीमारी का खतरा अधिक रहता है। इन राज्यों में गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, असम, गोवा, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान-निकोबार और दादरा एवं नगर हवेली व दमन-दीव को इस योजना के अंतर्गत रखा गया है।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बीमारी और इससे होने वाली मौतों को कम करना, समय पर पहचान और इलाज सुनिश्चित करना, मरीजों की बेहतर देखभाल करना और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। इसके तहत राज्यों को निगरानी मजबूत करने, जागरूकता बढ़ाने और जोखिम वाले क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं। केरल में बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आम लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है। साफ-सफाई बनाए रखना, जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचना, खुले घावों को ढककर रखना और बुखार या शरीर दर्द जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराना बेहद जरूरी माना जा रहा है। जिस तेजी से इस साल लेप्टोस्पायरोसिस ने जानलेवा रूप लिया है, वह यह स्पष्ट करता है कि इसे हल्के में लेना अब संभव नहीं है और सरकार तथा आम जनता दोनों को मिलकर इससे निपटने के लिए गंभीर कदम उठाने होंगे।

संपादकीय

पीड़ा से मुक्ति

देश में लंबे समय से यह मुद्दा सार्वजनिक विमर्श में रहा है कि विषम परिस्थितियों में एक त्रासदी से मुक्ति हेतु इच्छामृत्यु की अनुमति दी जाए या नहीं। समय-समय पर अदालती फैसलों ने मार्गदर्शक भूमिका निभाई है। साथ ही कोशिश की गई है कि इस छूट का दुरुपयोग न किया जा सके। हाल ही में एक ज्वलंत प्रसंग पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी थी कि हमें अब कुछ करना होगा, इस तरह के त्रासद जीवन की कोई तार्किकता नहीं है। दरअसल, यह मामला एक 32 वर्षीय युवक का है, जो पिछले 13 सालों से कोमा जैसी स्थिति में है। यह अब केवल महज चिकित्सीय त्रासदी का मामला नहीं रह गया है। अब यह एक महत्वपूर्ण कानूनी और नैतिक प्रश्न भी बन चुका है। निश्चित रूप से शीर्ष अदालत की टिप्पणी देश में जीवन के अंतिम क्षणों में गरिमापूर्ण व्यवहार के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। निश्चय ही यह प्रसंग अतीत में बहुचर्चित अरुणा शानबाग के मामले की यादें फिर से ताजा कर देता है। इस प्रसंग ने ही देश को पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु के प्रश्न का सामना करने के लिये बाध्य किया था। वर्ष 2011 में, सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग के मामले में फैसला सुनाते हुए, सैद्धांतिक रूप से निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी। दरअसल, अरुणा शानबाग एक भयानक हमले के बाद से ही 42 वर्षों से कोमा जैसी स्थिति में रही थीं। भले ही अदालत ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, लेकिन साथ ही उसके साथ कुछ प्रतिबंधात्मक सुरक्षा उपायों के अनुपालन के भी निर्देश दिए थे। निश्चित रूप से इस मामले में अदालती फैसला नैतिक प्रेरणा का स्रोत भी बना। कालांतर में जिसके चलते वर्ष 2018 में एक संविधान पीठ ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की। साथ ही इसके लिये एक आवश्यक प्रक्रिया भी निर्धारित की थी। जिसका मकसद था कि समाज में कहीं इस छूट का दुरुपयोग आपराधिक स्वार्थों के लिये न किया जा सके।

वर्ष 2023 में, अदालत ने इन दिशानिर्देशों को और सरल बनाने का प्रयास किया। जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि प्राथमिक और माध्यमिक चिकित्सा बोर्डों द्वारा स्थिति के मूल्यांकन की आवश्यकता रहेगी। फिलहाल देश में वही प्रक्रिया आज भी चल रही है। बहरहाल, वर्तमान मामले में बार-बार की गई अपीलें, इससे जुड़ी खामियों को भी उजागर करती हैं। दरअसल, ऐसे मामलों में पीड़ित को घर में दी जाने वाली देखभाल अपर्याप्त ही साबित होती है। वहीं दूसरी ओर राज्य का समर्थन भी पर्याप्त नहीं रहा है। इसके अलावा ऐसे मामलों से जुड़ी अनसुलझी नैतिक दुविधाएं असमंजस की स्थिति पैदा करती रही हैं। निस्संदेह, इस मामले में किसी युवा वयस्क के लिये निष्क्रिय इच्छामृत्यु की पहली स्पष्ट स्वीकृति हो सकती है। आज देश में हजारों मरीज कोमा जैसी अवस्था में नारकीय जीवन जी रहे हैं। जो उनके परिवारों के लिये भी एक त्रासदी की स्थिति है। जहां परिवार एक ओर भावनात्मक संकट से जूझ रहे होते हैं, वहीं रोगी के उपचार से जनित आर्थिक बोझ भी निरंतर बढ़ता जाता है। दूसरी ओर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार पर भी सवाल उठते रहे हैं। निस्संदेह, अदालत को जटिल परिस्थितियों में जैविक अस्तित्व के कठोर विस्तार के बजाय रोगी की मुक्ति और परिवार की पीड़ा को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसे में यदि एम्स 17 दिसंबर तक मामले में जीवन की निरर्थकता की पुष्टि करता है, तो निष्क्रिय इच्छामृत्यु की स्वीकृति एक मिसाल कायम कर सकती है। इसके बाद दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों को भी स्पष्ट किया जा सकेगा। साथ ही जीवन के अंतिम विकल्पों का सम्मान किया जा सकेगा। देश के नीति-नियंताओं को कोमा जैसी अवस्था में सालों जूझते लोगों के मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाने चाहिए, जिससे ऐसे रोगियों की उपचारात्मक देखभाल और परामर्श को एकीकृत किया जा सके। मानवीय करुणा की मांग है कि जीवन की पवित्रता और पीड़ा की क्रूरता के बीच संतुलन बनाया जाए। इच्छामृत्यु जब सहमति से होगी तो मानवता को कायम रखा जा सकता है। न्यायपालिका को ऐसा न्याय देना चाहिए, जो रोगी को पीड़ा से मुक्त करे और एक करुणामय भविष्य का मार्ग प्रशस्त करे।

डीपसीक गाथा में भारत के लिए मौजूद सबक

> डीपसीक की धूमधाम के तुरंत बाद, भारत ने बुनियादी मॉडल विकसित करने के लिए परियोजनाओं का एक समुच्चय घोषित किया। हालांकि डीपसीक व्यावसायिक उद्यम है, जिसका मकसद वैश्विक बाजारों में मुनाफा कमाना है। वहीं, भारतजेन रणनीतिक राष्ट्रीय मिशन है, जो तकनीकी संप्रभुता प्राप्ति पर केंद्रित है। इसके जरिये सार्वजनिक भलाई में संतुलन बनाकर चलना होगा।

इस वर्ष जनवरी में, एक अल्पज्ञात चीनी स्टार्टअप ने नाटकीय घोषणा की, जिसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की दुनिया को हिला दिया। कंपनी थी 'डीपसीक', जिसने अपने लार्ज लेंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम को अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों, जैसे कि चैट जीपीटी के विकसित मॉडलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए जारी किया।

जिस चीज़ ने सब को हैरान किया, वह था इसको विकसित करने में आई बेहद कम लागत, यह सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करके सिलिकॉन वैली के दिग्गजों द्वारा विकसित किए एआई की तुलना में अंश मात्र है। इस नई घटना ने दुनिया को दिखा दिया कि एआई क्षेत्र में चीन बहुत आगे है और अमेरिका तकनीकी विकास में एकमात्र प्रभावी शक्ति नहीं रहा। अब, विज्ञान पत्रिका 'नेचर' ने डीपसीक के संस्थापक लियांग वेनफेंग को 2025 के दौरान वैश्विक स्तर के प्रमुख वैज्ञानिक विकास के पीछे के शीर्ष 10 लोगों में नामित किया है।

डीपसीक का सामान्य उद्देश्य 'वी-3 मॉडल' और उन्नत मॉडल, 'आर-1' ने केवल सनसनीखेज सुर्खियां बटोरी बल्कि करीब एक वर्ष में एआई परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव भी लाए हैं। 'आर-1' एक तर्कशील एलएलएम है जो गणित और कोडिंग में जटिल कार्यों को संभाल सकता है। चीनी फर्म ने अमेरिकी कंपनियों से एक कदम आगे बढ़ते हुए डीपसीक को एक ओपन मॉडल बना दिया, जिसके तहत शोधकर्ताओं को विभिन्न क्षेत्रों के लिए मॉडल के एल्गोरिद्म अपने अनुसार अनुकूलित करने की अनुमति है। कंपनी ने यह राज़ भी खोला कि वह 'प्रशिक्षण' लागत इतनी कम कैसे रख पाई। सभी एलएलएम को पहले विशाल मात्रा में डेटा भरना पड़ता है या उन्हें कुशल बनाने के लिए 'डेटा-प्रशिक्षित' करना पड़ता है। एक उद्योग सर्वेक्षण से पता चला है कि इस वर्ष चीनी मॉडल एआई बाजार में तेजी से आगे बढ़े हैं,

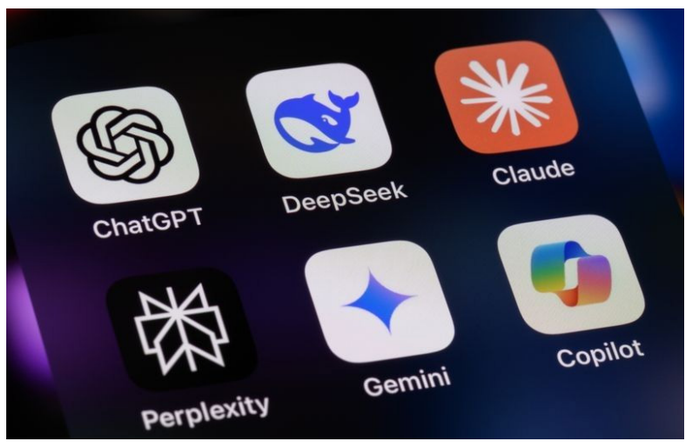

जिसकी बदौलत वे इस तकनीक के वैश्विक उपयोग का एक-तिहाई हिस्सा बन चुके हैं। टोकन वॉल्यूम में इंग्लिश के बाद चीनी भाषा के प्रॉम्प्ट दूसरे स्थान पर हैं। यह दर्शाता है, चीनी मॉडल वैश्विक स्तर पर अच्छा कर रहे हैं और चीन के भीतर भी व्यापक रूप से उपयोग किए जा रहे। टोकन डेटा की वे इकाइयां हैं जिन्हें एआई मॉडल द्वारा ट्रेनिंग और अनुमान के दौरान संसाधित किया जाता है व ये भविष्यवाणी, सृजन और तर्क को सक्षम करने में मदद करते हैं।

डीपसीक की धूमधाम के तुरंत बाद, भारत ने भी बुनियादी मॉडल विकसित करने के लिए परियोजनाओं का एक समुच्चय घोषित किया, जिसमें एलएलएम, लघुभाषा मॉडल और भारतीय आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त समस्या-विशिष्ट एआई समाधान शामिल हैं। इस योजना में 'डिजिटल इंडिया भाषिणी' (भारतीय भाषाओं के लिए एआई भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म), भारतजेन (सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए मल्टीमॉडल एलएलएम), सर्वम-1 एआई मॉडल (10 भारतीय भाषाओं के लिए एलएलएम), चित्रलेखा (वीडियो ट्रांसक्रिएशन प्लेटफॉर्म) और 'हनुमान'स एवरेस्ट' 1.0 (35 भारतीय भाषाओं के लिए बहुभाषाई एआई प्रणाली) का विकास करना शामिल है। प्रौद्योगिकी संस्थानों का संघ यानी 'भारतजेन' मुख्यालय आईआईटी-बॉम्बे में स्थापित किया गया है; इसे विभिन्न मंत्रालयों से वित्त पोषण के साथ 'संप्रभु बहुभाषी एलएलएम' विकास का कार्य सौंपा गया, जिसमें राष्ट्रीय एआई मिशन से 980 करोड़ रुपये शामिल हैं। यह वित्तीय मदद भारतजेन को एलएलएम विकसित करने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में पहला ऐसा उद्यम बनाती है।

चूंकि भारतीय घोषणा डीपसीक के ऐलान के तुरंत बाद आई, भारतजेन को चीनी पहल के सीधे जवाब के रूप में देखा गया। हालांकि, महत्वपूर्ण अंतर हैं। डीपसीक एक व्यावसायिक उद्यम है, जो स्टार्टअप मोड में निर्मित है और जिसका मंतव्य वैश्विक बाजारों में उपयोग है। वहीं, भारतजेन रणनीतिक राष्ट्रीय मिशन है, जो पूरा सरकार द्वारा वित्त पोषित होगा और तकनीकी संप्रभुता प्राप्ति पर केंद्रित है। चैट जीपीटी और डीपसीक जैसे वैश्विक मॉडलों की प्रमुख चुनौती भारत की जटिल भाषाई व सांस्कृतिक विविधता समझना है। भारतजेन यह अंतर भरने का प्रयास करेगा क्योंकि इसे भारतीय-विशिष्ट डेटा की विशाल मात्रा पर प्रशिक्षित किया जाएगा। डीपसीक के मॉडल सामान्य उद्देश्य के हैं और वैश्विक उपभोग के लिए बनाए हैं, जबकि भारतजेन भारत-विशिष्ट होगा। सबसे बड़ा अंतर यह है कि डीपसीक पहले से बाजार में है, जबकि भारतजेन ने अभी ठोस समय सीमा की घोषणा नहीं की। चैट जीपीटी, डीपसीक और अन्य ऐसे एलएलएम मॉडल विकसित करने वाली कंपनियों के विपरीत, भारतजेन वाणिज्यिक उद्यम नहीं। इसे इस महीने आईआईटी-बॉम्बे द्वारा एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया। भले यह पूरी तरह सरकारी वित्तपोषित है, तथापि यह एक कॉर्पोरेट इकाई होगा। आईआईटी प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन जो भारतजेन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के प्रमुख हैं, ने स्पष्ट किया कि एआई मॉडल को प्रयोगशाला से बाजार में लाया जा सके इसके लिए स्वायत्तता और संचालन लचीलापन आवश्यक है।

भारतजेन दिलचस्प उदाहरण है जिसे 'सरकारी उद्यमिता' कहा जा सकता है—1970 और 1980 के दशक का एक मॉडल। उस समय के दो सफलतम तकनीकी उद्यम -कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉर्पोरेशन (सीएमसी) और सेंटर फॉर टेलीमैटिक्स (सी-डॉट)- ने इस मॉडल का पालन किया। दोनों का गठन तकनीकी संप्रभुता स्थापित करना और रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए किया गया था। दोनों मामलों में, आईआईटी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जैसे शोध संस्थानों का योगदान अहम रहा। आधारभूत मॉडलों के विकास में भारतीय तकनीकी निजी कंपनियों की बेरुखी रोचक है, हालांकि निजी क्षेत्र ने डेटा केंद्रों जैसी एआई अवसंरचना बनाने में वैश्विक कंपनियों के साथ सहयोग करने के लिए उत्साह दिखाया। भारतीय तकनीकी सेवा उद्योग, जिसकी आय करीब 200 अरब डॉलर है, को तेजी से बदलते एआई परिदृश्य में मात्र दर्शक या बाहरी तकनीक अपनाने वाले के रूप में नहीं रहना चाहिए। इसके पास प्रतिभा, अनुभव और वित्तीय शक्ति है जिसका उपयोग भारतजेन जैसे राष्ट्रीय उद्यमों हेतु करना चाहिए। डीपसीक एक चीनी मात्रात्मक हेज फंड, हाई फ्लेयर के स्वामित्व वाला और वित्तपोषित है। दोनों कंपनियों के संस्थापक व सीईओ लियांगवेनफेंग हैं। इसे सरकार द्वारा वित्तीय मदद नहीं मिलती, लेकिन इसके द्वारा विकसित मॉडल सरकारी सेंसरशिप नियमों का पालन करते हैं। वर्तमान चीनी नियमों के अनुसार सभी एआई सेवाओं के लिए जरूरी है कि वे समाजवादी बुनियादी मूल्य प्रतिबिंबित करने वाली हो और उन्हें ऐसी सामग्री वितरित करने से बचना चाहिए जो 'राज्य शक्ति को कमजोर' करें' या 'राष्ट्रीय एकता को चोट पहुंचाने वाली' हों। यही वजह है, चीनी एआई मॉडल तियानमिन स्क्वायर प्रदर्शन, ताइवान की स्थिति, मानवाधिकार उल्लंघन और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व की आलोचना जैसे विषय पर चुप्पी साध लेते हैं या आधिकारिक दृष्टि प्रदान करते हैं।

भारत एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस, जो कि पिछले महीने जारी की गई थीं, 'जिम्मेदार एआई विकास' की बात कहती हैं और जवाबदेही, निष्पक्षता, सुरक्षा और मानव निगरानी की जरूरत रेखांकित करती हैं। राज्य-वित्त पोषित भारतजेन को सरकारी समर्थन और सार्वजनिक भलाई के बीच संतुलन बनाते हुए कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। इसके मॉडल को पश्चिमी मॉडलों में देखे गए एल्गोरिद्मिक पूर्वाग्रहों से बचना होगा और चीनी मॉडलों में मौजूद भ्रामक सूचनाओं व संभावित राजनीतिक प्रभाव से भी दूर रहना होगा।

प्रेरणा

जब घमंड की शेल्फ़ टूटी और इंसानियत बच गई

बहुत पुराने समय की बात है, प्राचीन जापान में एक ऐसा सम्राट शासन करता था जिसके वैभव और शानो-शौकत की मिसालें दी जाती थीं, लेकिन उसका स्वभाव उतना ही कठोर और निर्दयी था। उसके दरबार में भय का सन्नाटा पसरा रहता था। छोटी-सी भूल भी उसके क्रोध को भड़का देती थी और वह बिना किसी सोच-विचार के प्राणदंड तक सुना देता था। लोगों के मन में यह बात बैठ चुकी थी कि सम्राट की नजर में इंसानी जान से अधिक मूल्यवान उसकी वस्तुएँ और उसका अहंकार है।

महल के भीतर बीस अत्यंत दुर्लभ और सुंदर फूलदानों का संग्रह रखा गया था। वे फूलदान केवल सजावट नहीं थे, बल्कि सम्राट की शक्ति, प्रतिष्ठा और घमंड का प्रतीक थे। वह अकसर मेहमानों को उन्हें दिखाकर गर्व से मुस्कराता और यह जताता कि जैसा संग्रह उसके पास है, वैसा किसी और सम्राट के पास नहीं। उन फूलदानों की देखरेख करने वाले सेवक हर समय भय में रहते थे, क्योंकि एक छोटी-सी चूक भी उनके जीवन का अंत बन सकती थी।

एक दिन वही हुआ जिसका डर सबके मन में था। सफाई के दौरान एक सेवक

का हाथ फिसल गया और एक फूलदानी ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। महल में जैसे ही यह खबर फैली, सेवक का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पता था कि अब उसका अंत निश्चित है। सम्राट के सामने उसे पेश किया गया और बिना उसकी बात सुने, बिना यह जाने कि गलती अनजाने में हुई है, सम्राट ने फांसी का आदेश दे दिया। दरबारियों ने बहुत विनती की, दया की गुहार लगाई, लेकिन सम्राट के कानों पर जूँ तक नहीं रेंगी।

उसी समय दरबार में एक वृद्ध व्यक्ति आया, जिसकी चाल धीमी थी, लेकिन आँखों में अद्भुत साहस झलक रहा था। उसने कहा कि वह टूटी हुई फूलदानी को जोड़ने की कला जानता है और उसे पहले जैसी बना सकता है। सम्राट को लगा कि उसकी शान बच सकती है, इसलिए उसने वृद्ध को अपनी बाकी उन्नीस फूलदानियाँ दिखाईं और कहा कि यदि वह टूटी हुई फूलदानी को भी इनकी तरह बना देगा तो उसे मनचाहा इनाम मिलेगा।

लेकिन जैसे ही सम्राट की बात समाप्त हुई, उस वृद्ध ने अचानक अपनी लाठी उठाई और एक-एक कर सभी उन्नीस फूलदानियाँ तोड़ दीं। दरबार में कोलाहल मच गया। सम्राट गुस्से से आगबबूला हो उठा और चिल्लाकर बोला कि उसने यह विनाश क्यों किया। तब उस वृद्ध ने अत्यंत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि वह जानता था कि हर फूलदानी के पीछे एक निर्दोष इंसान की जान छिपी है। उसने यह भी कहा कि अगर ये फूलदान आज नहीं टूटते, तो कल इनके कारण और लोगों की जान जाती। उसने अपने इंसान होने का कर्तव्य निभाया है और उन्नीस लोगों के प्राण बचाए हैं। अब यदि सम्राट चाहे तो उसे फांसी दे सकता है।

वृद्ध के शब्द तीर की तरह सम्राट के हृदय में चुभ गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका घमंड किस हद तक अमानवीय बन चुका है। उसे यह भी समझ में आया कि उसकी सनक ने वस्तुओं को जीवन से ऊपर स्थान दे दिया है। उस क्षण उसकी आँखें झुक गईं। उसने न केवल उस सेवक को, बल्कि उस निडर वृद्ध को भी क्षमा कर दिया।

उस दिन महल में एक भी फूलदानी नहीं बची, लेकिन सम्राट के भीतर जमी क्रूरता की परतें टूट गईं। उसे यह सच्चाई समझ में आ गई कि सच्चा वैभव सोने-चाँदी या दुर्लभ वस्तुओं में नहीं, बल्कि उस करुणा में है जो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए अपने हृदय में स्थान देता है। उस घटना ने यह अमिट संदेश छोड़ दिया कि जब घमंड की शेल्फ़ टूटती है, तभी इंसानियत सुरक्षित रहती है।

छोटे निर्यातकों की सुध ले सरकार, ई-कामर्स निर्यात यात्रा डिजिटल निर्भरता की कहानी न बने

भारत आज अपने निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। देश के छह करोड़ से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विश्व के सबसे बड़े कारीगर, शिल्पकार और छोटे उद्यमी समुदाय की आधारशिला हैं। इन छोटे उद्यमियों, हथकरघा बुनकरों और हस्तशिल्प कलाकारों को ई-कामर्स निर्यात के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंचने का एक नया और प्रभावी मार्ग मिला है।

अंतरराष्ट्रीय आनलाइन प्लेटफार्मों ने भारत के छोटे विक्रेताओं को बिना किसी विदेशी कार्यालय के दुनिया के 200 से अधिक देशों में उपभोक्ताओं तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। डिजिटल बाजार और भारत की रचनात्मक, किफायती उत्पादन प्रणाली ने वैश्विक व्यापार में छोटे भारतीय विक्रेताओं के लिए अवसरों का विस्तार किया है। पिछले एक दशक में ई-कामर्स आधारित डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर माडल ने भारत के छोटे उत्पादकों को उल्लेखनीय सशक्तीकरण दिया है।

इस माडल में उत्पाद विदेशी ग्राहकों द्वारा आर्डर मिलते ही सीधे भारत से भेजे जाते हैं, जिससे प्रवेश लागत कम होती है और घर-आधारित उद्यमी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुरू कर पाते हैं। भारत के हस्तशिल्प, वस्त्र, आभूषण, प्राकृतिक और पारंपरिक उत्पादों की वैश्विक मांग बढ़ रही है। यह माडल विशेषकर छोटे उद्यमों के लिए आय और पहचान का स्रोत बना है, भले ही उन्हें कस्टम्स, भुगतान निपटान और कर संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो।

अब एक नया परिवर्तन इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाला है। बड़े वैश्विक ई-कामर्स भारत से वेयरहाउस आधारित निर्यात माडल की अनुमति चाहते हैं, जिसमें भारतीय विक्रेता माल को मार्केट प्लेस के घरेलू वेयरहाउस में जमा करेंगे और उसके बाद मार्केट प्लेस स्वयं इन उत्पादों का निर्यात कर उन्हें विदेश में बेचेगा।

उक्त परिवर्तन भारतीय विक्रेताओं की भूमिका को बदल देगा। वे अब निर्यातक नहीं रहेंगे, बल्कि केवल घरेलू आपूर्तिकर्ता बनकर रह जाएंगे। निर्यातक के रूप में मार्केट प्लेस मूल्य निर्धारण, इन्वेंटरी, विदेशी वितरण और फारेक्स प्राप्ति पर पूरा नियंत्रण रखेगा। हालांकि चीन, वियतनाम और मलेशिया सरीखे देशों में यह माडल पहले से अपनाया जा रहा है, लेकिन भारतीय संदर्भ में इनके गहरे और दीर्घकालिक प्रभाव चिंताजनक हैं। वेयरहाउस माडल से छोटे विक्रेताओं का मूल्य निर्धारण पर नियंत्रण समाप्त हो सकता है, क्योंकि मार्केट प्लेस सभी आपूर्तिकर्ताओं की लागत संरचना जानकर कीमतों पर दबाव डाल सकता है। इससे छोटे विक्रेता "प्राइस-टेकर" बन जाएंगे और उनके लाभांश में भारी कमी हो सकती है। विदेशी बाजार में मिलने वाला पूरा रिटेल मार्जिन मार्केट प्लेस अपने पास रख सकता है, जबकि भारतीय विक्रेता को केवल थोक दर प्राप्त होगी, जो अंतिम बिक्री मूल्य का एक छोटा हिस्सा होती है।

इस माडल का प्रभाव यह भी है कि भारत के निर्यात मूल्य में वास्तविक कमी आ सकती है। आज जब एक भारतीय विक्रेता सीधे 2,000 रुपये की कालीन विदेश में बेचता है, तो पूरे 2,000 रुपये भारत के फारेक्स में दर्ज होते हैं, परंतु वेयरहाउस माडल में वही कालीन 1,100–1,200 रुपये में मार्केट प्लेस द्वारा खरीदी जाएगी और इसी राशि को भारत के निर्यात मूल्य के रूप में दर्ज किया जाएगा।

इससे न केवल भारत के आधिकारिक निर्यात मूल्य घटेंगे, बल्कि कई मामलों में मार्केट प्लेस अपने विदेश स्थित सहायक कंपनियों के माध्यम से मुनाफा भी विदेश में दर्ज कर सकते हैं, जिससे भारत का कर आधार भी कम होगा। जैसे-जैसे मार्केट प्लेस कम दरों पर बड़े पैमाने पर खरीद करेगा, लाखों कारीगरों का लाभ कम हो सकता है। लाभ में कमी आने पर कई उद्यमी गुणवत्ता से समझौता कर सकते हैं, जिससे भारत की वैश्विक ब्रांड प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। जब निर्यात मार्केट प्लेस के नाम पर होगा तो भारतीय उत्पादों की पहचान एवं विशिष्टता खो सकती है।

भारत की व्यापार और एमएसएमई नीति लंबे समय से आत्मनिर्भरता, मूल्य संवर्धन और डिजिटल सशक्तीकरण पर आधारित रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और विदेशी व्यापार नीति जैसी पहलें छोटे उद्यमियों को वैश्विक बाजार से सीधे जोड़ने की दिशा में काम कर रही हैं।

ऐसे में वेयरहाउस माडल उस उद्देश्य से भी उलट है, जिसका लक्ष्य डिजिटल बाजारों का लोकतंत्रीकरण है। भारत के लिए नीति-निर्माण में संतुलन बनाना आवश्यक है, लेकिन छोटे निर्यातकों की स्वायत्तता और पहचान खोकर नहीं। भारत चाहे तो पीपीपी माडल के तहत तटस्थ ई-कामर्स एक्सपोर्ट हब विकसित कर सकता है, जो एमएसएमई के उत्पादों को एकत्र कर निर्यात में मदद करें, पर निर्यातक वही रहें।

वेयरहाउस माडल सतही रूप से सुविधाजनक दिखाई देता है, लेकिन यह भारत के जमीनी निर्यात ढांचे को कमजोर कर सकता है और लाखों उद्यमियों को साधारण आपूर्तिकर्ता में बदल सकता है। भारत की ई-कामर्स निर्यात यात्रा अब तक डिजिटल समावेशन, महिला सशक्तीकरण और रचनात्मक उद्यमिता की कहानी रही है। यह सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि यह आगे चलकर डिजिटल निर्भरता की कहानी न बन जाए।

भारत को विदेशी प्लेटफार्म-प्रधान वेयरहाउस माडल नहीं, एक सशक्त और मूल्य-साझा करने वाला डिजिटल निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र चाहिए। छोटे निर्यातकों की रक्षा करना किसी संरक्षणवाद का संकेत नहीं है, बल्कि एक आत्मनिर्भर, समावेशी और मूल्य केंद्रित निर्यात भविष्य के लिए आवश्यक आर्थिक दूरदर्शिता है।

अभियान

देव दर्शन के बाद शरीर और मन से जुड़ा शास्त्रीय अनुशासन

हिंदू धर्म में मंदिर को केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा का केंद्र माना गया है। यह विश्वास है कि मंदिर में प्रवेश करते ही व्यक्ति एक ऐसी सूक्ष्म शक्ति के प्रभाव में आ जाता है, जो सीधे उसके मन, शरीर और आत्मा को स्पर्श करती है। घंटियों की ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण, धूप–दीप की सुगंध और श्रद्धा से भरा वातावरण मिलकर एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इसी कारण शास्त्रों में मंदिर दर्शन के बाद कुछ नियमों का पालन करने की परंपरा बताई गई है, जिनका उद्देश्य उस सकारात्मक प्रभाव को यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखना होता है।

अक्सर देखा जाता है कि लोग मंदिर से लौटते ही घर के बाहर या अंदर पहुंचते ही तुरंत हाथ-पैर धो लेते हैं। यह व्यवहार सामान्य सफाई की दृष्टि से स्वाभाविक लग सकता है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इसे उचित नहीं माना गया है। शास्त्रों के अनुसार मंदिर का वातावरण अत्यंत पावन और सात्त्विक होता है। वहां की ऊर्जा व्यक्ति के चरणों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है और पूरे शरीर में फैल जाती है। माना जाता है कि यदि दर्शन के तुरंत बाद पानी से हाथ-पैर धो लिए जाएं, तो वह दिव्य प्रभाव जल्दी समाप्त हो सकता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि मंदिर से आने के बाद कुछ समय तक पानी को न छुआ जाए, ताकि वह ऊर्जा शरीर और मन में स्थिर हो सके।

धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि मंदिर से लौटने के बाद व्यक्ति को कुछ देर शांत भाव से बैठना चाहिए। उस समय मन को इधर-उधर भटकने देने के बजाय भगवान के स्वरूप, उनके नाम और दर्शन के भाव को स्मरण करना चाहिए। यह समय आत्मिक स्थिरता का होता है, जिसमें मंदिर में प्राप्त शांति और सकारात्मकता भीतर गहराई तक उतरती है। ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति इस ऊर्जा को अनुभव करते हुए कुछ देर मौन या ध्यान की अवस्था में रहता है, तो उसका मानसिक तनाव कम होता है और दिनभर के कार्यों में शुभ फल प्राप्त होते हैं।

ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि से मंदिर की ऊर्जा व्यक्ति की आभा को भी सशक्त करती है। आभा का संबंध व्यक्ति के आत्मबल, सोच और कर्मों से होता है। मंदिर दर्शन के बाद यह आभा कुछ समय के लिए विशेष रूप से तेज और शुद्ध होती है। यदि इस अवस्था में तुरंत स्नान कर लिया जाए या बार-बार पानी का प्रयोग किया जाए, तो यह प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। इसी कारण शास्त्रों में मंदिर से लौटते ही स्नान करने को भी अच्छा नहीं माना गया है। माना जाता है कि स्नान का उद्देश्य बाहरी और आंतरिक अशुद्धियों को दूर करना होता है, जबकि मंदिर दर्शन स्वयं एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। इसलिए दोनों के बीच कुछ समय का अंतर होना चाहिए।

मंदिर से लौटकर व्यक्ति को अपने घर में प्रवेश करने के बाद कुछ क्षण भगवान का स्मरण करना चाहिए, मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए और यह अनुभव करना चाहिए कि जो शांति और सकारात्मकता उसने मंदिर में महसूस की थी, वह अब उसके भीतर भी विद्यमान है। यह अभ्यास धीरे-धीरे व्यक्ति के स्वभाव में स्थिरता, संयम और श्रद्धा को बढ़ाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से घर का वातावरण भी सात्त्विक होता है और परिवार में सौहार्द बना रहता है।

इस प्रकार मंदिर दर्शन केवल एक बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि एक आंतरिक साधना है। दर्शन के बाद अपनाया गया यह अनुशासन उस साधना को पूर्ण करता है। जब व्यक्ति थोड़ी देर तक उस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर समाहित होने देता है, तभी मंदिर जाना सार्थक माना जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में मंदिर से लौटने के बाद संयम, शांति और नियमों के पालन पर विशेष बल दिया गया है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

जामनगर में प्रभारी मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया की अध्यक्षता में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित

▸▸ जिला स्तरीय कार्यक्रम में जामनगर की 9 कंपनियों द्वारा 5716 करोड़ के एमओयू किए गए

▸▸ उद्योगपति संपत्ति के सृजनकर्ता और देश की प्रगति के प्रमुख वाहक हैं: प्रभारी मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया

(जीएनएस)। गांधीनगर : जामनगर में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की श्रृंखला के अंतर्गत राज्य के वन एवं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माननीय मंत्री तथा जामनगर जिले के प्रभारी मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया की अध्यक्षता में लेउआ पाटीदार समाज भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान जिला उद्योग केंद्र और विभिन्न 9 कंपनियों के बीच कुल 5716 करोड़ की राशि के एमओयू का आदान-प्रदान किया गया। इनमें विंड-सोलर पावर हाइब्रिड प्रोजेक्ट (नवीकरणीय ऊर्जा) सेक्टर में ओपविंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (3368 करोड़), जामनगर रिन्यूएबल्स वन एंड टू प्राइवेट लिमिटेड (1703 करोड़) तथा सुजलॉन वेस्टर्न इंडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड (600 करोड़) द्वारा आगामी तीन वर्षों में विंड-सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स को क्रियान्वित किया जाएगा। इन परियोजनाओं के माध्यम से अनुमानित रूप से 1725 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

इसके अलावा, इंजीनियरिंग, ऑटो एवं अन्य उद्योग क्षेत्रों में शिव ओम ब्रास इंडस्ट्रीज (25 करोड़), मेटालेक्स एक्सट्रूज़न (6.5 करोड़), एटलस मेटल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (5 करोड़), रेमबेम पी.जी.एम. इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (5 करोड़) तथा यल्लो गोल्ड मेटल प्राइवेट लिमिटेड (3.5 करोड़) द्वारा एल्युमिनियम एक्सट्रूज़न प्लांट, एल्युमिनियम एवं कॉपर लग्स, ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग, केमिकल प्रोडक्ट्स और ब्रास पार्ट्स के क्षेत्रों में परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। इनसे अनुमानित रूप से 400 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इन सभी परियोजनाओं के वर्ष 2026 में प्रारंभ होने की संभावना है। इसके साथ ही माननीय मंत्री द्वारा श्री वाजपेयी बैंकेबल योजना के लाभार्थियों को व्यवसाय हेतु लोडिंग वाहनों की चाबियां भी प्रदान की गईं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये गुजरात के विकास की दृष्टि, आत्मनिर्भरता के संकल्प और विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रारंभ की गई वाइब्रेंट गुजरात पहल ने आज गुजरात को वैश्विक निवेशकों के लिए एक पसंदीदा केंद्र बना दिया है।

जामनगर जिला औद्योगिक दृष्टि से एक विशिष्ट पहचान रखता है। चाहे ब्रास पार्ट उद्योग हो या निर्माण क्षेत्र, रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग हों, बंदरगाह आधारित गतिविधियाँ हों या पारंपरिक कारीगरी, जामनगर ने हमेशा विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। यहाँ के उद्योगपतियों की मेहनत और कौशल ने जामनगर को 'ब्रास सिटी ऑफ इंडिया' के रूप में पहचान दिलाई है।

राजकोट में आयोजित होने वाली रीजनल समिट के माध्यम से राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर मौजूद औद्योगिक संभावनाओं की पहचान करना, स्थानीय उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करना और रोजगार सृजन को और अधिक गति देना है। यह विशेष रूप से एमएसएमई, स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों और युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है।

श्री अर्जुनभाई मोढवा डिया ने आगे कहा कि उद्योगपति संपत्ति के सृजनकर्ता और देश की प्रगति के प्रमुख वाहकों में से एक हैं। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में उद्योगपतियों की अहम भूमिका होती है। जामनगर में ऑयल रिफाइनरी, निर्माण कार्यक्षेत्र और ब्रास पार्ट उद्योगों के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। जामनगर के उद्योगपतियों ने तकनीकी उन्नयन और बाजार अनुसंधान के साथ आधुनिक तकनीकों को अपने व्यवसाय में अपनाया है। गुजरात को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

जामनगर जिले में आने वाले दिनों में नए उद्योगों, नई तकनीकों और नए रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध होने की प्रबल संभावनाएं हैं। ऐसे में माननीय मंत्री द्वारा राजकोट में आयोजित होने वाली वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में जामनगर जिले के उद्योगपतियों से सक्रिय सहभागिता करने की अपील की गई।

शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रिवाबा जाडेजा ने कहा कि बांधणी उद्योग जामनगर की सांस्कृतिक पहचान है। जामनगर में बांधणी उद्योग के चलते महिलाओं को रोजगार मिला है और वे आत्मनिर्भर बनी हैं। जामनगर की बांधणी को प्राप्त जीआई टैग तथा जामनगर के ब्रास पार्ट उद्योग में कार्यरत कारीगरों और उद्योगपतियों की मेहनत के परिणामस्वरूप यहाँ इसरो और नासा जैसी संस्थाओं के लिए भी ब्रास पार्ट्स का निर्माण हुआ है, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। जामनगर का ब्रास पार्ट उद्योग और बांधणी उद्योग दोनों ही गुजरात की आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि का सशक्त प्रतीक हैं। एक ओर आधुनिक उद्योगों से रोजगार और निर्यात में वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक कला के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी हो रहा है। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस गुजरात सरकार की दूरदर्शिता, विकास के प्रति प्रतिबद्धता और सर्वांगीण प्रगति का सशक्त प्रतिबिंब है। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों की ताकत, संभावनाओं और स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होगा। उद्योगपतियों की सफलता की गाथाओं की प्रस्तुति के अंतर्गत जामनगर फैक्ट्री ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रामजीभाई गढ़िया तथा मैसर्स माइक्रोटेक मेटल इंडस्ट्रीज के श्री अशोकभाई डोमडिया ने ब्रास उद्योग से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। इसके पश्चात विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात स्टार्टअप इकोसिस्टम, एसएमई इनोवेशन लाइक ए कॉर्पोरेट इनोवेशन, ग्लोबल परिदृश्य एवं निर्यात, क्रेडिट लिंकेज सेमिनार, पीएमएफएमई योजना, युवाओं को कौशल प्रदान करना एवं रोजगार के अवसर सृजित करना, वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस पर प्रस्तुति तथा जिला उद्योग केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में लगभग 25 विभिन्न स्टॉलों की प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें ब्रास पार्ट्स से संबंधित स्टॉल, बांधणी के स्टॉल, हस्तकला के स्टॉल सहित विविध क्षेत्रों के स्टॉल शामिल थे। माननीय मंत्रीगण एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों ने इन स्टॉलों का अवलोकन किया तथा संबंधित प्रतिनिधियों से संवाद कर उनकी जानकारी प्राप्त की।

कार्यक्रम के दौरान iNDEXTb के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री के. सी. संपत द्वारा प्रासंगिक उद्बोधन प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती मेयबेन गरसर, विधायक श्री दिव्येशभाई अकबरी, कलेक्टर श्री केतन ठक्कर, जिला विकास अधिकारी श्री अंकित पन्नु, डिप्टी मेयर श्रीमती कृष्णाबेन सोंढा, एएसपी श्रीमती प्रतिभा, अग्रणी समाजसेवी श्रीमती बीनाबेन कोठारी एवं डॉ. विनोदभाई भंडेरी, चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री रमणिकभाई अकबरी, जीआईडीसी फेज़ 2 एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विष्णुभाई पांभर, लघु उद्योग भारती एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जयेशभाई संघाणी, जामनगर सहकारी उद्योग संघ लिमिटेड के अध्यक्ष श्री धीरजलाल कारिया, एम. पी. शाह म्यूनिसिपल उद्योगनगर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सरदारसिंह जाडेजा सहित विभिन्न एसोसिएशनों के पदाधिकारी, अधिकारीगण, उद्योगपति तथा आमंत्रित अतिथि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

सामान्य सर्दी के पीछे छिपा खतरा, दिल की सेहत पर भारी पड़ सकता है आरएसवी वायरस

(जीएनएस)। अक्सर बदलते मौसम में होने वाली सर्दी, खांसी और जुकाम को लोग मामूली परेशानी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिक शोध यह चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसी लापरवाही भारी पड़ सकती है। डेनमार्क के स्टेटेंस सीरम इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण अध्ययन में सामने आया है कि रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, जिसे आमतौर पर आरएसवी कहा जाता है और जो सामान्य सर्दी-जुकाम का कारण बनता है, वह केवल सांस की बीमारी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दिल की गंभीर और जानलेवा बीमारियों का जोखिम भी बढ़ा सकता है। इस अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि आरएसवी संक्रमण के बाद दिल का दौरा, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर जैसी समस्याओं की आशंका उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाती है।

आरएसवी एक बेहद सामान्य लेकिन अत्यधिक संक्रामक वायरस है, जो हर साल पतझड़ और सर्दियों के मौसम में फ्लू की तरह तेजी से फैलता है। यह वायरस खांसी और छींक के दौरान निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। इतना ही नहीं, यह वायरस विभिन्न सतहों पर करीब सात घंटे तक जीवित रह सकता है, जिससे संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। ब्रिटेन जैसे विकसित देश में भी हर साल लगभग 30,000 बच्चों और 18,000 वयस्कों को आरएसवी संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। आंकड़ों के अनुसार, करीब 8,000 वयस्कों की मौत के पीछे भी यही वायरस एक प्रमुख कारण माना जाता है, जो इसकी गंभीरता को दर्शाता है।

इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने 45 वर्ष से अधिक उम्र के 17,000 से ज्यादा मरीजों के आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण किया। शोध में पाया गया कि जिन लोगों को आरएसवी संक्रमण हुआ था, उनमें संक्रमण के एक साल के भीतर दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा स्पष्ट रूप से अधिक था। सामान्य रूप से देखा जाए तो आरएसवी संक्रमण के बाद एक साल के भीतर दिल की बीमारी होने का जोखिम लगभग 4.7 प्रतिशत तक बढ़ गया। जिन लोगों को पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर, धमनियों में रुकावट या अन्य हृदय रोग थे, उनमें यह खतरा और भी ज्यादा बढ़कर 11.9 प्रतिशत तक पहुंच गया। अस्पताल में भर्ती होने वाले आरएसवी मरीजों में दिल से जुड़ी जटिलताओं का जोखिम 6.6 प्रतिशत तक पाया गया, जबकि 85 से 94 वर्ष की उम्र के बुजुर्गों में यह बढ़ोतरी 7.9 प्रतिशत तक देखी गई।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह शोध इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि आरएसवी केवल बच्चों या कमजोर फेफड़ों वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि बुजुर्गों और पहले से दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों ने योग्य लोगों को आरएसवी वैक्सीन लगवाने की सलाह दी है। यह वैक्सीन 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध है और बुजुर्गों को आरएसवी के कारण अस्पताल में भर्ती होने से करीब 82 प्रतिशत तक बचाने में सक्षम मानी जा रही है। शोध में यह भी बताया गया है कि गर्भवती महिलाओं को यह टीका लगवाने से उनके शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी गर्भस्थ शिशु तक पहुंच जाती हैं। इससे बच्चे को जन्म के बाद शुरुआती छह महीनों तक सुरक्षा मिलती है और बच्चों में आरएसवी के कारण अस्पताल में भर्ती होने के लगभग 72 प्रतिशत मामलों को रोका जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रिसर्च लोगों की सोच बदलने वाली है, क्योंकि जो वायरस अब तक सिर्फ सामान्य सर्दी-जुकाम से जोड़ा जाता था, वह वास्तव में दिल के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। इस अध्ययन का संदेश साफ है कि सर्दी, खांसी और जुकाम को हमेशा हल्के में नहीं लेना चाहिए, खासकर बुजुर्गों और पहले से दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों को। समय पर सावधानी, लक्षणों पर ध्यान और वैक्सीनेशन जैसे कदम न केवल संक्रमण से बचाव कर सकते हैं, बल्कि दिल की गंभीर बीमारियों के खतरे को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं।

सप्ताह के दौरान सोना वायदा में 2391 रुपये और चांदी वायदा में 20804 रुपये का ऊछाल: क्रूड ऑयल वायदा 204 रुपये फिसला

कमोडिटी वायदाओं में 359185.31 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 1803312.3 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 261454.80 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 32563 पॉइंट के स्तर पर

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 5 से 11 दिसंबर के सप्ताह के दौरान कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 2162557.67 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 359185.31 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 1803312.3 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिसंबर वायदा 32563 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 34415.85 करोड़ रुपये का हुआ।

आलोच्य अवधि के सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 261454.80 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 129897 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 132574 रुपये के ऑल टाइम हाई और 129101 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 130078 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 2391 रुपये या 1.84 फीसदी की तेजी के संग 132469 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा सप्ताह के अंत में 1509 रुपये या 1.45 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 105706 रुपये प्रति 8 ग्राम पर बंद हुआ। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 191 रुपये या 1.46 फीसदी की तेजी के संग 13239 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर सप्ताह के अंत में पहुंचा। सोना-मिनी जनवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 128785 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 130988 रुपये के उच्च और 127833 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 2011 रुपये या 1.56 फीसदी की मजबूती के साथ 130905 रुपये प्रति 10 ग्राम बंद हुआ। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम सप्ताह के आरंभ में 129048 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 131290 रुपये के उच्च और 128140 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 129192 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 1945 रुपये या 1.51 फीसदी की बढ़त के साथ 131137 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 179509 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 199220 रुपये के ऑल टाइम हाई और नीचे में 179200 रुपये पर पहुंचकर, 178138 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 20804 रुपये या 11.68 फीसदी ऊछलकर 198942 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 20273 रुपये या 11.33 फीसदी की तेजी के संग 199210 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 20280 रुपये या 11.33 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 199223 रुपये प्रति किलो पर सप्ताह के अंत में बंद हुआ।

मेटल वर्ग में 28459.67 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा सप्ताह के अंत में 38.25 रुपये या 3.56 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 1111.85 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 11.85 रुपये या 3.84 फीसदी की मजबूती के साथ सप्ताह के अंत में 320.1 रुपये प्रति किलो बंद हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम दिसंबर वायदा 2.45 रुपये या 0.88 फीसदी बढ़कर 280.7 रुपये प्रति किलो के भाव पर सप्ताह के अंत में बंद हुआ। जबकि सीसा दिसंबर वायदा सप्ताह के अंत में 1.15 रुपये या 0.63 फीसदी घटकर 181.9 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 69252.56 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल दिसंबर वायदा 5363 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 5449 रुपये और नीचे में 5160 रुपये पर पहुंचकर, सप्ताह के अंत में 204 रुपये या 3.79 फीसदी गिरकर 5179 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी दिसंबर वायदा 201 रुपये या 3.74 फीसदी की गिरावट के साथ सप्ताह के अंत में 5180 रुपये प्रति बैरल के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा नैचुरल गैस दिसंबर वायदा 453.2 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 494.9 रुपये और नीचे में 380 रुपये पर पहुंचकर, 447.4 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 66.3 रुपये या 14.82 फीसदी गिरकर 381.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी दिसंबर वायदा 66.3 रुपये या 14.81 फीसदी लुढ़ककर 381.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू सप्ताह के अंत में बंद हुआ।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा 904 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के अंत में 7.8 रुपये या 0.86 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 911 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सप्ताह के दौरान सोना के विभिन्न अनुबंधों में 108824.90 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 152629.90 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 22994.57 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 1707.58 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 328.54 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 3423.64 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 7630.96 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 61532.02 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 12.29 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सप्ताह के अंत में सोना के वायदाओं में 13255 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 46169 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 7499 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 121041 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 13249 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 12532 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 30751 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 74466 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 11849 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 22188 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स दिसंबर वायदा सप्ताह के आरंभ में 31172 पॉइंट पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 33407 के उच्च और 31000 के नीचले स्तर को छूकर, 1553 पॉइंट बढ़कर 32563 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ।

मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने शहरी विकास वर्ष के उत्सव के अंतर्गत सूरत वासियों को 600 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भेंट दी

▸▸ सूरत महानगर पालिका और सुडा के 249 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 109.51 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अर्बन रिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूआरडीसीएल) के अनुमानित 242 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया

▸▸ प्रधानमंत्री की विजनरी लीडरशिप का लाभ आज पूरे देश के साथ गुजरात को मिल रहा है, सभी शहरी जन स्वच्छता को अपना स्वभाव बनाएं: मुख्यमंत्री

(जीएनएस)। गांधीनगर : राज्यों के शहरों के विकास को गति देने तथा शहरी जनों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने शनिवार को 'शहरी विकास वर्ष–2025' के उत्सव के अंतर्गत सूरत महानगर पालिका और सुडा (सूरत शहरी विकास प्राधिकरण) के कुल 249 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 109.51 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने अर्बन रिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूआरडीसीएल) द्वारा साकार होने वाले अनुमानित 242 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के कन्वेंशन हॉल में आयोजित समारोह में सूरत वासियों को 600 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विजनरी लीडरशिप का लाभ आज पूरे देश के साथ गुजरात को मिल रहा है। सूरत के साथ पूरा गुजरात तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पूरे देश में स्वच्छता के क्षेत्र में सूरत ने अपनी पहचान बनाई है। इस दौरान श्री पटेल ने सभी लोगों से स्वच्छता को स्वभाव में अपनाने का आग्रह किया। सूरत का आउटडोर रिंग रोड पूर्ण होने से ट्रैफिक में कमी के साथ लोगों की सुविधाओं में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में सामान्य व्यक्ति को केंद्र में रखकर विकास आगे बढ़ रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि एक समय था जब एक लाख रुपए के कार्य के लिए भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जबकि आज एक करोड़ रुपए के कार्य आसानी से हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षा के पैटर्न में बदलाव आया है, ऐसे में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने सभी से वृक्षारोपण कर ग्रीन कवर बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने वर्षा जल के पूर्ण उपयोग से जल संचय मां सभी की भागीदारी की भी अपेक्षा व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के कारण आज कच्छ एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बना है। एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क खावड़ा में साकार हुआ है। ईज ऑफ लिविंग कैसे बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। एक समय राज्य के समुद्र तटों के प्रति उदासीनता थी, आज गुजरात का समुद्र तट समृद्धि का गेट-वे बन गया है।

सूरत जिला प्रभारी एवं वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने कहा कि वर्ष 2025–26 में राज्य के शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार ने 30 हजार करोड़ रुपए का बड़ा बजट आवंटित किया है। नई महानगर पालिकाओं के विकास के लिए भी राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। महानगर पालिकाओं के नव-गठन के साथ ही बजट उपलब्ध कराया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि गुजरात में शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, जिसके अनुरूप आधारभूत सुविधाओं और व्यवस्थाओं की अग्रिम योजना बनाई गई है। भरूच और उमरगाम के बीच सूरत विकास का केंद्र बिंदु है, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में विकास और पर्यटन से बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है। सूरत विश्व के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में से एक है।

महानगर पालिका कमिश्नर श्रीमती शालिनी अग्रवाल ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि सूरत शहर के नए क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए 600 करोड़ रुपए के विकास कार्य उपयोगी सिद्ध होंगे। वर्ष 2025 को शहरी विकास वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। 'अर्निंग वेल और लिविंग वेल' के मंत्र के साथ रीजनल डेवलपमेंट के छह प्लान के अंतर्गत दक्षिण गुजरात का विकास विजन शीघ्र ही लॉन्च किया जाएगा, जो विकास का एक महत्वपूर्ण रोडमैप बनेगा।

सार्वजनिक सेवाओं के डिजिटलाजेशन, जल प्रबंधन में सुधार, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में वृद्धि तथा शहर के आधारभूत नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए विकास कार्यों की सौगात दी गई। सूरत महानगर पालिका के विभिन्न जोन में बने प्रमुख कार्यों में वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, गंदे पानी के निपटान के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ड्रेनेज लाइन, हेल्थ सेंटर, फायर स्टेशन, वेंडिंग मार्केट तथा वर्षा जल निकासी के लिए बॉक्स कल्वर्ट सहित के कार्यों का शिलान्यास किया गया।

अर्बन रिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट फेज–2 के अंतर्गत 184.20 करोड़ रुपए की लागत से सचिन–पलसाणा से सचिन कडोदरा जंक्शन आउटर रिंग रोड का कार्य तथा 57.65 करोड़ रुपए की लागत से सूरत–कडोदरा रोड आउटर रिंग रोड पर फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण कार्य का शिलान्यास शामिल है।

सूरत शहरी विकास प्राधिकरण (सुडा) द्वारा शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न टीपी स्कीमों के तहत चार लेन सड़कों, डामर रोड, सड़कों के रिसर्फेसिंग कार्यों का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को साकार करते हुए सूरत महानगर पालिका द्वारा नागरिकों को मनपा की विभिन्न सेवाएं सरल, तेज और पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट की ऑनलाइन पेमेंट सुविधा का लॉन्च किया। कृषि मंत्री जीतूभाई वाघाणी, सांसद श्री मुकेश दलाल, मेयर दक्षेश मावाणी, विधायक श्री पूर्णेश मोदी, श्री संदीप देसाई, श्री ईश्वर परमार, श्री कांतीभाई बलर, श्री संगीता बेन पाटील, उप महापौर नरेन्द्र पाटील, स्थायी समिति के चेयरमैन श्री राजन पटेल, जिला कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी, कॉरपोरेटर सहित पदाधिकारी व शहरीजन उपस्थित रहे।

इंजीनियरिंग कार्य हेतु लिए गए ब्लॉक के

(जीएनएस)। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा चुरू–आसलू–दूधवा खारा स्टेशनों के मध्य पैच डबलिंग कार्य एवं स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली के कमीशनिंग कार्य हेतु लिए गए ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल से होकर संचालित भावनगर–हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन को पूर्णतः निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व में लिए गए डायवर्जन के निर्णय को निरस्त करते हुए यात्रियों की सुरक्षा एवं परिचालनिक कारणों से इस ट्रेन को पूर्णतः निरस्त किया गया है।

निरस्त की जाने वाली ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1.दिनांक 19.01.2026 एवं 22.01.2026 को भावनगर टर्मिनस से चलने वाली ट्रेन संख्या 19271 भावनगर–हरिद्वार एक्सप्रेस पूर्णतः निरस्त रहेगी।

2.दिनांक 21.01.2026 एवं 24.01.2026 को हरिद्वार से चलने वाली ट्रेन संख्या 19272 हरिद्वार–भावनगर एक्सप्रेस पूर्णतः निरस्त रहेगी।

यात्रियों की सुविधा हेतु आरक्षित यात्रियों को एसएमएस अलर्ट भेजे जाएंगे तथा सूचना विभिन्न माध्यमों से प्रचारित की जा रही है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अद्यतन जानकारी के लिए NTES ऐप पर निगरानी रखें अथवा भारतीय रेल की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें । यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए रेल प्रशासन खेद प्रकट करता है।

पश्चिम रेलवे द्वारा कलोल स्टेशन पर चार ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव

(जीएनएस)। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की बहुप्रतीक्षित मांग को ध्यान में रखते हुए वलसाड–वडनगर एक्सप्रेस, जोधपुर–केएसआर बेंगलुरु एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर–साबरमती एक्सप्रेस और दिल्ली सराय रोहिल्ला–बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेनों का कलोल स्टेशन पर प्रायोगिक आधार पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इन ट्रेनों का कलोल स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान का समय निम्नानुसार रहेगाः

1. ट्रेन संख्या 20959/20960 वलसाड–वडनगर-वलसाड सुपरफास्ट एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 20959 वलसाड–वडनगर एक्सप्रेस 16 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 11.37 बजे आगमन एवं 11.39 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 20960 वडनगर-वलसाड एक्सप्रेस 16 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 18.15 बजे आगमन एवं 18.17 बजे प्रस्थान करेगी।

2. ट्रेन संख्या 12215/12216 दिल्ली सराय रोहिल्ला–बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 12215 दिल्ली सराय रोहिल्ला–बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस 16 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 22.41 बजे आगमन एवं 22.43 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 12216 बांद्रा टर्मिनस-दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीब रथ एक्सप्रेस 16 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 20.11 बजे आगमन एवं 20.13 बजे प्रस्थान करेगी।

3. ट्रेन संख्या 16507/16508 जोधपुर–केएसआर बेंगलुरु द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 16507 जोधपुर–केएसआर बेंगलुरु एक्सप्रेस 18 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 12.55 बजे आगमन एवं 12.57 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 16508 केएसआर बेंगलुरु-जोधपुर एक्सप्रेस 17 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 06.19 बजे आगमन एवं 06.21 बजे प्रस्थान करेगी।

4. ट्रेन संख्या 15269/15270 मुजफ्फरपुर–साबरमती साप्ताहिक जनसाधारण एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 15269 मुजफ्फरपुर–साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस 20 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 05.53 बजे आगमन एवं 05.55 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 15270 साबरमती-मुजफ्फरपुर जनसाधारण एक्सप्रेस 20 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 18.28 बजे आगमन एवं 18.30 बजे प्रस्थान करेगी।

ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे - अहमदाबाद मण्डल

पुराने स्टील रिवेटेड गर्डर्स का नये कॉम्पोजीट गर्डर्स द्वारा रिगर्डरींग और जेकेटींग द्वारा पुराने उप–ढांचे का सशक्तिकरण

ई–निविदा सूचना सं. 15 वर्ष 2025–26 दिनांक : 12/12/2025

ई–निविदा सं. डीवायसीई–बीआर–एडीआई–13–2025–26

कार्य का नामः अहमदाबाद मंडल – वरि. अनुभाग अभियंता (पुल) अहमदाबाद के क्षेत्राधिकार आधिन गेरतपुर–अहमदाबाद स्टेशन के बीच पु. सं. 711 UP और DN के मौजुदा पुराने स्टील रिवेटेड गर्डर्स का नये कॉम्पोजीट गर्डर्स द्वारा रिगर्डरींग और जेकेटींग द्वारा पुराने उप–ढांचे का सशक्तिकरण करने का कार्य ।

NIT की अनुमानित लागतः ₹ 6,33,09,976.22

बीड सुरक्षा लागत/ ईएमडीः ₹ 4,66,600.00

ई–निविदा बंद होने की तिथि एवं समयः दिनांकः 13/01/2026 को 15:00 बजे

कार्यालय का पताः उप मुख्य अभियंता (पुल) अहमदाबाद, मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर, गुजरात कैंसर सोसायटी अस्पताल के सामने, असारवा, नरोडा रोड, अमदुपुरा, अहमदाबाद, गुजरात–380016.

ई–निविदा में भाग लेने हेतु वेबसाईटः www.ireps.gov.in

ADI-230

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: x.com/WesternRly

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सूरत में 'ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल' की 116वीं नेशनल एग्जीक्यूटिव बैठक का शुभारंभ किया

▶▶ देश के 16 राज्यों के महानगरों के महापौर एवं राज्य के शहरी विकास मंत्री श्री कनुभाई देसाई सहभागी हुए

▶▶ शहरों का सर्वग्राही आर्थिक, सामाजिक विकास तथा स्मार्ट, सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट प्रधानमंत्री

▶▶ द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का मजबूत आधार है: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

-:मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

▶▶ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शहरीकरण की चुनौतियों को अवसर में बदलकर गुजरात में वर्ष 2005 में 'शहरी विकास वर्ष' से मॉडर्न अर्बन डेवलपमेंट मॉडल की पहल की

▶▶ 2005 के 'शहरी विकास वर्ष' की दो दशक की सफलता के परिणामस्वरूप वर्ष 2025 को 'शहरी विकास वर्ष' के रूप में मनाने से शहरों की स्वच्छता और फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट में गति आई है

▶▶ प्रधानमंत्री के दिशादर्शन में गुजरात ने सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से शहरों के समग्र विकास के लिए 'स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना' की पहल की

▶▶ प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए इन्क्लूसिव ग्रोथ के विचार को साकार करने के लिए छोटे शहरों के विकास को भी गति देते हुए नई महानगर पालिकाओं का गठन किया गया

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने स्पष्ट रूप से कहा कि शहरों का सर्वग्राही आर्थिक, सामाजिक विकास तथा स्मार्ट, सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने का मजबूत आधार है।

शनिवार को सूरत में आयोजित अखिल भारतीय 'मेयर्स परिषद' की 116वीं कार्यकारिणी बैठक के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अध्यक्ष के तौर पर संबोधित किया। शहरी विकास एवं वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई, देश के 16 राज्यों के महानगरों के महापौर तथा परिषद के पदाधिकारी इस कार्यकारिणी बैठक में सहभागी हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शहरीकरण की चुनौतियों को अवसर में बदलकर गुजरात में वर्ष 2005 में शहरी विकास वर्ष के माध्यम से मॉडर्न अर्बन डेवलपमेंट मॉडल की शुरुआत की थी।

वेल प्लांड सिटी डेवलपमेंट के लिए बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को इसके परिणामस्वरूप गति मिली और 2005 के 'शहरी विकास वर्ष' की दो दशक की सफलता के चलते राज्य सरकार ने भी वर्ष 2025 को 'शहरी विकास वर्ष' के रूप में मनाया। श्री पटेल ने जोड़ा कि 2025 के इस 'शहरी विकास वर्ष' में शहरों की स्वच्छता तथा फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट में तेजी आई है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 'मेयर्स परिषद' में शहरी विकास योजनाओं और लोगों के ईज ऑफ लिविंग में वृद्धि करने वाली गुजरात के इनिशिएटिव्स की प्रभावशाली प्रस्तुति की।

इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन से शहरों के सर्वग्राही विकास के लिए 'स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना' की पहल गुजरात ने की है। इस योजना में भौतिक सुविधाएं, सामाजिक आधारभूत संरचना के साथ अर्बन ग्रीन मोबिलिटी, 'मुख्यमंत्री शहरी सड़क योजना' को प्राथमिकता देने से ईज ऑफ लिविंग बढ़ा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात ने देश को शहरी क्षेत्रों में बीआरटीएस जनमार्ग और ई-सिटी बस सेवाओं का सफल मॉडल दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत अनेक आइकॉनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है, जिनमें सूरत डायमंड बोर्स तथा रिवरफ्रंट गौरव के प्रतीक बने हैं।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए इन्क्लूसिव ग्रोथ के विचार को साकार करने के लिए छोटे शहरों के विकास को भी गति दी गई है। राज्य में नई नौ महानगर पालिकाओं का गठन किया गया है और बड़े महानगरों की महानगर पालिकाओं ने इन नई महानगर पालिकाओं का हैंड होल्डिंग कर हॉलिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का विकास किया है।

मुख्यमंत्री ने विकसित गुजरात की भूमिका को दर्शाते हुए कहा कि 2047 तक 'विकसित भारत' के प्रधानमंत्री के लक्ष्य को पूरा करने में गुजरात को अग्रसर बनाए रखने के लिए 'अर्निंग वेल-लिविंग वेल' मंत्र के साथ 'विकसित गुजरात @2047' का रोडमैप तैयार किया है। इस अवसर पर शहरी विकास तथा वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने उपस्थित सभी महापौरों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि शहरीकरण की चुनौती को अवसर मानकर जल प्रबंधन, स्वच्छता, शिक्षा, आवास, सीवेज और ग्रीन एनर्जी सहित के कार्य करने से निश्चित रूप से सुसंचालित नगर नियोजन किया जा सकता है। उन्होंने जोड़ा कि पूरे देश में ग्रीन एनर्जी राज्य के रूप में तेजी से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई सोलर योजना में गुजरात की उपलब्धि अब अन्य राज्यों के लिए प्रेरणास्वरूप बनी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने 48 प्रतिशत शहरीकरण का लक्ष्य हासिल किया है तथा वर्ष 2047 तक 75 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में गुजरात तेजी से आगे बढ़ रहा है। 'अखिल भारतीय मेयर्स परिषद' की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती रेणूबाला गुप्ता ने अपने प्रासंगिक संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में गुजरात ने पूरे देश को विकास का एक नया मार्ग दिखाया है तथा गुजरात को देश के लिए रोल मॉडल बनाया है, जिससे अन्य नगरों के महापौरों को स्वच्छ, स्मार्ट व सुविधासंपन्न नगर के विकास के लिए मार्गदर्शन मिलेगा।

प्रासंगिक संबोधन में 'अखिल भारतीय मेयर्स परिषद' के महामंत्री श्री आशुतोष ने परिषद की स्थापना, कार्यों और उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी तथा शहरी विकास में परिषद के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला।

इस अवसर पर महापौर श्री दक्षेशभाई मावाणी ने कहा कि सूरत ने स्वच्छता, जल प्रबंधन और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उन्होंने जोड़ा कि विकास के निरंतर नए आयामों के साथ आगे बढ़ता सूरत देश के कई शहरों के लिए सकारात्मक सुधारों के माध्यम से अन्य शहरों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा।

इस अवसर पर गुजरात की महानगर पालिकाओं के महापौर, सांसद श्री मुकेशभाई दलाल, विधायक श्री प्रविणभाई घोघारी, पूर्णेशभाई मोदी, संगीताबेन पाटील, पूर्व मंत्री श्री दर्शनाबेन जरदोश, सूरत महा नगरपालिका आयुक्त श्रीमती शालिनी अग्रवाल, कलेक्टर श्री सौरभ पारधी, उप महापौर श्री नरेन्द्रभाई पाटिल, स्थायी समिति अध्यक्ष श्री राजनभाई देसाई, शहर संगठन प्रमुख श्री परेशभाई पटेल, मनपा में शासक पक्ष की नेता श्रीमती शशिबेन त्रिपाठी, सचेतक श्री धर्मेश वाणियावाला सहित सूरत महानगर पालिका के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सूरत एपीएमसी द्वारा निर्मित राज्य के पहले एलिवेटेड मार्केट यार्ड का उद्घाटन किया

▶▶ टू-वे रैम्प वाली बिल्डिंग में हैं अत्याधुनिक सुविधाएं : भारी वाहन पहली मंजिल तक सीधे दुकानों के सामने पहुंच सकते हैं

▶▶ राज्य के किसानों को सहूलियत, सुरक्षा और कृषि उपजों का उचित मूल्य मिले, ऐसी पारदर्शी और आधुनिक व्यवस्था विकसित की जा रही है : कृषि एवं सहकारिता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी

▶▶ सूरत एपीएमसी मार्केट के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण के हिस्से के रूप में एलिवेटेड मार्केट यार्ड का निर्माण

▶▶ मार्केट यार्ड में आने वाले किसानों, व्यापारियों और श्रमिकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक उपचार केंद्र और बीज वितरण केंद्र का लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

▶▶ श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी और एआई का उपयोग करके खेती में उत्पादन, सस्टेनेबिलिटी और बाजार की उपलब्धता बढ़ रही है

▶▶ 1951 में केवल 15 हजार रुपए की आय के साथ शुरू हुई सूरत एपीएमसी आज सहकारिता के वटवृक्ष में बदल गई है

▶▶ राज्य सरकार 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र के साथ कृषि में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दे रही है

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार समिति (एपीएमसी) सूरत की ओर से नवनिर्मित राज्य के सबसे बड़े और सर्वप्रथम एलिवेटेड यानी पहली मंजिल तक भारी वाहनों का आवागमन सुनिश्चित करने वाले अत्याधुनिक मार्केट यार्ड का लोकार्पण किया।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने सूरत एपीएमसी मार्केट के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण के हिस्से के रूप में निर्मित इस अत्याधुनिक एलिवेटेड मार्केट यार्ड में आने वाले किसानों, व्यापारियों और श्रमिकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक उपचार केंद्र और बीज वितरण केंद्र का भी लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने एलिवेटेड स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए एपीएमसी की सराहना की, जिसमें बड़े ट्रक और भारी वाहनों की आसान आवाजाही तथा प्रवेश एवं निकास का इस प्रकार सुव्यवस्थित आयोजन किया गया है कि आने वाले कई वर्षों तक कोई अव्यवस्था नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 1951 में केवल 15 हजार रुपए की आय के साथ शुरू हुई सूरत एपीएमसी आज सहकारिता के वटवृक्ष में बदल गई है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के अधिकतम उपयोग के जरिए किसानों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र के साथ देश में अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करके सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाया गया है, जिससे किसानों और पशुपालकों की आय और जीवन स्तर को सुधारने वाले महत्वपूर्ण कार्य को और व्यापक और गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सका है।

मुख्यमंत्री ने संपूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत और पारदर्शी व्यवस्था तथा यहां कृषि उपजों की बिक्री के लिए आने वाले किसानों को आरटीजीएस के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बधाई दी। उन्होंने इस बात की भी सराहना की कि इन सुविधाओं के चलते महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों के किसान भी यहां अपनी कृषि उपज बेचने के लिए आकर्षित हुए हैं।

उन्होंने गर्व से कहा कि रोजाना 12 से 15 हजार लोगों की आवाजाही के साथ यह मार्केट यार्ड पिछले दो वर्षों से आय की दृष्टि से गुजरात में अव्वल स्थान पर है और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र के साथ प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में कृषि में मूल्य संवर्धन की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रही है। सरकार ने एग्रो और फल प्रसंस्करण श्रृंखला स्थापित कर आम, चीकू, सब्जियों और लहसुन आदि के लिए स्पेशल एग्री एक्सपोर्ट जोन भी विकसित किए हैं।

उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करके खेती में उत्पादन, सस्टेनेबिलिटी और बाजार की उपलब्धता बढ़ रही है। किसान ई-मित्र जैसी एआई-आधारित सेवाओं के जरिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के बारे में आसान भाषा में जानकारी मिल रही है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई बेमौसम बारिश के बाद राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए घोषित किया गया दस हजार करोड़ रुपए का बड़ा कृषि सहायता पैकेज किसानों को इस संकट से उबारने में बहुत उपयोगी साबित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान मानधन, पर ड्रॉप-मोर क्रॉप, नेशनल बाम्बू मिशन ओर नमो ड्रोन दीदी सहित लगभग 28 से अधिक योजनाओं एवं अभियानों के जरिए खेती एवं किसान विकास को नई दिशा दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्लाइमेट चेन्ज के विरुद्ध लड़ाई के लिए प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दे रही है, जो भूमि, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। प्राकृतिक खेती से किसानों की आय में वृद्धि और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने सभी से स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ विकसित गुजरात से विकसित भारत की ओर आगे बढ़ने का आह्वान किया।

इस अवसर पर कृषि एवं सहकारिता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि राज्य सरकार और सहकारी क्षेत्र इस बात का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को नई सुविधाएं, आधुनिक व्यवस्थाएं और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और उनकी आय में वृद्धि हो। इसका जीवंत उदाहरण सूरत की एपीएमसी मार्केट है। उन्होंने इस मार्केट में आधुनिकता के साथ-साथ किसान-उन्मुख सुविधाएं और व्यवस्थाएं विकसित करने के लिए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं।

कृषि मंत्री ने कहा कि सूरत एपीएमसी मार्केट यार्ड राज्य का सबसे अधिक कमाई करने वाला यार्ड है, जो सहकारिता की शक्ति का बेहतरीन उदाहरण है। यह कमाई किसी एक व्यक्ति या संस्था की नहीं, बल्कि पूरी सहकारी व्यवस्था और किसानों की है। उन्होंने अतीत की विकट स्थिति की याद दिलाते हुए कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में राज्य के मार्केट यार्डों में उचित शेड, बारिश या मौसम संबंधित परिस्थितियों में कृषि उत्पादों को रखने की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज मार्केट यार्डों की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। अब ऐसी पारदर्शी और आधुनिक व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं, जिनमें किसानों को सहूलियत, सुरक्षा और कृषि उत्पादों का समुचित मूल्य मिलता है।

विधायक और सूरत एपीएमसी के चेयरमैन संदीपभाई देसाई ने स्वागत भाषण में कहा कि सूरत एपीएमसी में देश के 15 राज्यों से किसान और बागायतदार अपने उत्पाद बेचने के लिए आते हैं। अत्याधुनिक एलिवेटेड मार्केट यार्ड में 100 फुट चौड़ा रैम्प बनाया गया है, जिससे टैम्पो और ट्रक जैसे वाहन सीधे पहली मंजिल पर दुकानों के सामने जाकर खड़े हो सकते हैं। इस सुविधा से कृषि उपजों को लाने-ले जाने में लगने वाले समय की बचत होगी और यातायात की समस्या से निजात मिलेगी तथा कृषि उपजों को सीधे व्यापारियों की दुकानों पर उतारा जा सकेगा।

श्री देसाई ने कहा कि एलिवेटेड मार्केट यार्ड के लिए केंद्र सरकार ने 19 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। मार्केट यार्ड की पहली मंजिल पर 108 हाईटेक दुकानें हैं, जिनमें विशाल स्टोर रूम, मार्केट में पहली मंजिर तक किसान और व्यापारी अपने वाहन लेकर जा सकें, इसके लिए टू-वे रैम्प, माल-समान ले जाने के लिए लिफ्ट, पैसेंजर लिफ्ट, आरसीसी रोड, पहली मंजिल पर 200 कार और 4000 दोपहिया वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग एरिया, मार्केट यार्ड में आने वाले किसानों, व्यापारियों तथा श्रमिकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक उपचार केंद्र और किसान मित्रों के लिए बीज वितरण केंद्र जैसी सुविधाएं किसानों और वेंडर्स के लिए स्थापित की गई हैं। कार्यक्रम में वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई, आदिजाति विकास मंत्री श्री नरेशभाई पटेल, सांसद श्री मुकेशभाई दलाल, प्रभुभाई वसावा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री भाविनीबेन पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश, विधायक सर्वश्री कुंवरजीभाई हळपति, गणपतसिंह वसावा, मोहनभाई ढोडिया, ईश्वरभाई परमार, विनोदभाई मोरड़िया, अरविंदभाई राणा, कांतिभाई बलर, मनुभाई पटेल, एपीएमसी उपाध्यक्ष श्री हर्षद पटेल, सूरत सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री भीखाभाई पटेल, सहकारी अग्रणी श्री रमणभाई जानी, एपीएमसी के निदेशकगण, जिला संगठन प्रमुख श्री भरत राठोड़, कई अग्रणी और किसान बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

विरमगाम स्टेशन का व्यापक पुनर्विकास : यात्रियों के लिए आधुनिक, सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्टेशन की दिशा में बड़ा कदम

2000 वर्गफीट का विशाल कंकॉर्स, 5000 वर्गफीट का पार्किंग क्षेत्र और 1460 वर्गफीट के डीलक्स प्रतीक्षालय का होगा समावेश

(जीएनएस)। भारतीय रेलवे में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, 160 स्टेशनों का कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें से गुजरात के 87 स्टेशन शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री ने इसी साल मई महीने में बीकानेर से 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया। जिसमें सामाख्याली सहित गुजरात के 18 स्टेशन शामिल है।

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल का विरमगाम स्टेशन एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। विरमगाम रेलवे स्टेशन का व्यापक पुनर्विकास 46.13 करोड़ की लागत से तेजी से किया जा रहा है। वर्तमान में विरमगाम स्टेशन पर 50 से अधिक ट्रेनें रुकती है। यहाँ से प्रतिदिन लगभग 7000 यात्री आवागमन करते है। इसे अगले 45-50 वर्ष के यात्री भार को ध्यान में रखते हुए पुनर्विकसित किया जा रहा है। विरमगाम स्टेशन पर 40 फीट चौड़ा नया फुट ओवर ब्रिज भी बनाया जा रहा है जो प्लेटफॉर्मों के बीच सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करेगा।

यह स्टेशन अहमदाबाद–विरमगाम, विरमगाम–सुरेंद्रनगर, विरमगाम–मेहसाणा और विरमगाम–ध्रांगध्रा–समाखियाली इन चार रेल मार्गों के जंक्शन पर स्थित है। यहाँ गेटवे डिस्ट्रिपार्क्स द्वारा इनलैंड कंटेनर डिपो सुविधा भी उपलब्ध है। जून 2023 में विरमगाम से मुंद्रा पोर्ट तक डबल-स्टैक रेल परिवहन सेवाएँ शुरू कीं, जिसका उद्देश्य अपने निर्यात-आयात (EXIM) व्यापार ग्राहकों के लिए परिचालन दक्षता बढ़ाना और लॉजिस्टिक लागत कम करना है।

विरमगाम स्टेशन का पुनर्विकास कार्य यात्री सुविधाओं, सुरक्षा तथा स्टेशन के सौंदर्यीकरण को ध्यान में रखते हुए तेजी से प्रगति पर है। यह कार्य स्टेशन को आधुनिक, सुरक्षित तथा दिव्यांगजन अनुकूल बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

पूर्ण किए गए कार्य

▶▶ नए स्टेशन भवन की संरचना का कार्य पूर्ण हो चुका है।

▶▶ नए स्टेशन भवन का प्लास्टर एवं टाइल्स लगाने का कार्य पूरा हो गया है।

▶▶ प्लेटफॉर्म पर शेड (शेल्टर) का कार्य पूरा कर लिया गया है।

▶▶ पुराने फुट ओवर ब्रिज (FOB) को सुरक्षित रूप से हटाया जा चुका है।

▶▶ नए विद्युत खंभों (इलेक्ट्रिक मस्त) की नींव का कार्य पूरा हो चुका है।

प्रगति पर कार्य

▶▶ नए स्टेशन भवन में आंतरिक एवं शेष समापन कार्य प्रगति पर है।

▶▶ यात्रियों के सुगम आवागमन के लिए नए फुट ओवर ब्रिज (FOB) का निर्माण कार्य जारी है।

▶▶ स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया तथा पार्किंग क्षेत्र का विकास कार्य जारी है।

▶▶ प्लेटफॉर्म सतह में सुधार का कार्य किया जा रहा है, जिससे चलने में सुविधा और सुरक्षा बढ़ेगी।

▶▶ स्टेशन पर प्रकाश व्यवस्था के उन्नयन हेतु नए विद्युत खंभों एवं हाई मस्त लाइट्स की स्थापना का कार्य चल रहा है।

▶▶ दिव्यांगजन के लिए टैक्टाइल टाइल्स, साइनज, हैंड रेल, समर्पित पार्किंग आदि सुविधाओं के विकास का कार्य प्रगति पर है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन (क्षेत्र/आकार):

▶▶ 4400 वर्गफीट की विशाल स्टेशन बिल्डिंग यात्रियों को आधुनिक एवं सुव्यवस्थित सुविधाएँ प्रदान करेगी।

▶▶ 20-20 फीट चौड़े प्रवेश/निकास द्वार यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाएंगे।

▶▶ 5000 वर्गफीट का पार्किंग क्षेत्र अधिक वाहनों को समायोजित करेगा।

▶▶ 13 फीट चौड़ी पिक-अप/ड्रॉप-ऑफ लेन वाहनों की आवागमन व्यवस्था को बेहतर बनाएगी।

▶▶ 2200 वर्गफीट का पोर्च यात्रियों को मौसम से सुरक्षा एवं आरामदायक प्रवेश प्रदान करेगा।

▶▶ 2000 वर्गफीट का विशाल कंकॉर्स यात्रियों को अधिक विस्तृत और आरामदायक स्थान उपलब्ध कराएगा।

▶▶ प्लेटफॉर्मों पर लिफ्ट और एस्केलेटर्स का प्रावधान

▶▶ प्लेटफॉर्म नं 2 और 3 की लंबाई में 100 फीट तक विस्तार

▶▶ 336 वर्गफीट का प्रतीक्षालय बैठने और विश्राम के लिए आरामदायक सुविधा प्रदान करेगा।

▶▶ 570 वर्गफीट का कैफेटेरिया साफ-सुथरे एवं सुविधाजनक भोजन विकल्प उपलब्ध कराएगा।

▶▶ 730 वर्गफीट के डीलक्स एसी एवं नॉन-एसी प्रतीक्षालय शांत और आरामदायक वातावरण में प्रतीक्षा की सुविधा देंगे।

▶▶ प्लेटफॉर्म 1 से 5 तक 38000 वर्गफीट क्षेत्र में कवर शेड यात्रियों को मौसम से सुरक्षा प्रदान करेगा।

▶▶ 430 वर्गफीट का शौचालय ब्लॉक स्वच्छता एवं सुविधा को और बेहतर बनाएगा।

▶▶ दिव्यांगजन हेतु 03 समर्पित पार्किंग स्लॉट उनकी पहुँच और सुविधा को और बेहतर बनाएंगे।

विस्तृत सर्कुलेटिंग एरिया के विकास से स्टेशन परिसर में वाहनों की आवाजाही अधिक सुव्यवस्थित होगी, जिससे स्टेशन तक पहुँचने और बाहर निकलने की सुविधा में सुधार होगा। उन्नत प्रतीक्षालय बेहतर बैठने की सुविधा, उचित वेंटिलेशन और शांत वातावरण प्रदान करेंगे, जिससे यात्रा अनुभव अधिक सुखद बनेगा।

आकृति आर्ट फाउंडेशन द्वारा 23 वीं अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का 16 दिसम्बर से मुंबई में आयोजन

(जीएनएस)। मुंबई, 13 दिसम्बर। देश की प्रमुख सांस्कृतिक, सामाजिक और कलात्मक संस्था *"आकृति आर्ट फाउंडेशन"* द्वारा अपनी 23 वीं अंतर्राष्ट्रीय समूह कला प्रदर्शनी का आयोजन मुंबई में 16 दिसम्बर, 2025 से 21 दिसम्बर, 2025 तक किया जा रहा है।

यह जानकारी देते हुए आकृति आर्ट फाउंडेशन के संस्थापक डायरेक्टर मनमोहन जायसवाल ने बताया कि यह संस्था पिछले 18 वर्षों से कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती रही है। इसी क्रम में संस्था की 23 वीं अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित मेकर चैम्बर्स की आर्ट गैलेरी में लगाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दुबई और पोलैंड से तकरीबन 40 प्रतिष्ठित कलाकार भाग ले रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि वे प्रत्येक वर्ष दो आर्ट एग्जिबिशंस का आयोजन करते हैं। इनमें देश- विदेश से आने वाले कलाकारों को अपनी खूबसूरत कला के प्रदर्शन का सुअवसर मिलता है। साथ ही उनकी संस्था विभिन्न अवॉर्ड शो, म्यूजिकल शो और आध्यात्मिक इवेंट्स का भी आयोजन करती आई है। उन्होंने बताया कि वे जल्दी ही अपनी टीम के साथ सभी कलाकारों के लिए डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी शुरू करने जा रहे हैं, जिससे आसानी से दुनिया के किसी भी कोने तक कलाकारों की कृतियाँ पहुँचाई जा सकती हैं। 23 वीं प्रदर्शनी में सुविख्यात चित्रकार एम एफ हुसैन, जामिनी रॉय, एस एच राजा, सोहन कुमार, पूर्वा तेनानी, प्रियेश, प्रधन्या पंडित, अनीता गोयल, संजना रामचंदानी, वैशाली शाह, प्रवीण पांडे, निशा गांधी, सलोनी गुप्ता, शोभना मेहता, सुनामदिनी जयंत, राजवी गांधी, निराली मोदी, राखी संघवी, रितिका सिंह, शेखर बर्वे, नंदा पाठक, सुमेध उन्नावने मयूर श्रीवंधनकर, नवाब जहान, तानिया फटनानी, ध्यानज्योति निंबालकर, शिवानी धुरिया, प्रीति शाह, आरती चोरड़िया, रूपाली मिस्त्री और श्रुति सोमन की पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया जायेगा। प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में बहुत से कला प्रेमी, इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट तथा संगीत और साहित्य जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। दीप प्रज्ज्वलन के साथ इस भव्य प्रदर्शनी की शुरुआत होगी। यह प्रदर्शनी 16 से 21 दिसम्बर, 2025 तक रोज़ाना दोपहर 12 से रात्रि 8 बजे तक सभी कलाप्रेमी दर्शकों के निःशुल्क अवलोकनार्थ खुली रहेगी।

पंकज चौधरी का निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय, योगी आदित्यनाथ के प्रस्ताव से भाजपा संगठन में नया अध्याय

(जीएनएस)। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से सात बार सांसद रह चुके पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग सुनिश्चित हो गया है। शनिवार को उन्होंने लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया और चूंकि उनके अलावा किसी अन्य नेता ने नामांकन नहीं किया है, इसलिए उनके निर्विरोध चुने जाने की पूरी संभावना बन गई है। औपचारिक घोषणा आज किए जाने की तैयारी है, जिसे लेकर पार्टी संगठन में उत्साह और सक्रियता साफ दिखाई दे रही है। नामांकन के दौरान पार्टी मुख्यालय का माहौल पूरी तरह राजनीतिक गर्मजोशी से भरा रहा। पंकज चौधरी ने अपना नामांकन पत्र प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उनके प्रस्तावक के रूप में मौजूद रहे, जो इस पूरे घटनाक्रम को और भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना देता है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता इस मौके पर उपस्थित रहे। सभी नेताओं की मौजूदगी ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया कि पंकज चौधरी को पार्टी नेतृत्व का पूरा समर्थन प्राप्त है।

प्रदेश भाजपा की ओर से जानकारी दी गई है कि नए प्रदेश अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा रविवार को लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान की जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए पार्टी ने व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया को विधिवत पूरा कराने के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी लखनऊ पहुंच चुके हैं। पार्टी संगठन इसे एक

बड़े राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में देख रहा है, जिसमें संगठनात्मक एकजुटता और आगामी चुनावों की रणनीति का संकेत भी मिलेगा।

प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी स्पष्ट किया है कि अध्यक्ष पद के लिए केवल एक ही नामांकन प्राप्त हुआ है, इसलिए रविवार को विधिवत रूप से नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी ने इस अवसर को खास बनाने के लिए लखनऊ महानगर के कार्यकर्ताओं को स्वागत और कार्यक्रम प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी है। अलग-अलग व्यवस्थाओं के लिए टीमें गठित की गई हैं, जिससे कार्यक्रम को सुचारू और प्रभावशाली ढंग से संपन्न कराया जा सके।

पंकज चौधरी का राजनीतिक सफर लंबा और अनुभव से भरा रहा है। महाराजगंज लोकसभा सीट से वे अब तक सात बार सांसद चुने जा चुके हैं, जो अपने आप में उनकी राजनीतिक पकड़ और जनाधार को दर्शाता है। उनका जन्म 20 नवंबर 1964 को गोरखपुर में हुआ था। राजनीति में उनकी शुरुआत वर्ष 1989 में गोरखपुर नगर निगम के पार्षद के रूप में हुई, जहां वे उपमहापौर भी रहे। वर्ष 1990 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और 1991 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। इसके बाद 1996, 1998, 2004, 2014, 2019 और 2024 में उन्होंने जीत दर्ज की, हालांकि 1999 और 2009 में उन्हें चुनावी हार का भी सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उनका राजनीतिक कद लगातार मजबूत होता गया।

वर्तमान समय में पंकज चौधरी केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और विभिन्न संसदीय समितियों में भी सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। पूर्वांचल क्षेत्र में उनकी छवि एक प्रभावशाली और जमीनी नेता की रही है, खासकर कुर्मी समाज और अन्य पिछड़ा वर्गों के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। यही कारण है कि पार्टी सूत्रों का मानना है कि उनके नेतृत्व में प्रदेश संगठन को नई ऊर्जा और नई दिशा मिल सकती है।

राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना भाजपा की आने वाली रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। गोरखपुर क्षेत्र से आने वाले चौधरी को पूर्वांचल में एक मजबूत संगठनकर्ता के रूप में देखा जाता है। पार्टी नेतृत्व आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन को और अधिक मजबूत करने की दिशा में यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपने जा रहा है।